रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 10, 1979/फाल्गुन 19, 1900
No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 10, 1979/PHALGUNA 19, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1979

का०आ० 829.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 209-सिकन्दराबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री वी० के० रंगा नयाकुलु, निवासी म० न० 12-1-1622, शान्ती नगर, उत्तरी लल्लागुड्डा, सिकन्दराबाद (आन्ध्र प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा / दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री वी० के० रंगा नयाकुलु, को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० आ०प्र० वि०स० /209/78]
वी० नागसुब्रमण्यम, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 5th February, 1979

S.O. 829.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri V. K. Ranga Nayakulu, resident of H. No. 12-1-1622, Shanthi Nagar, North Lallagudda, Secunderabad (Andhra Pradesh), a contesting candidate for general election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in February, 1978 from 209-Secunderabad constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri V. K. Ranga Nayakulu to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-LA/209/78]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

ERRATA

New Delhi, the 23rd February, 1979

S.O. 830.—In the English Version of the Election Commission's Notification No. 282/1/PB/78, dated 22nd January, 1979, published in the Extraordinary issue of the Gazette of India, Part II-Section 3(ii) dated 31st January, 1979 as S.O. 60(E).—

(i) At page 110 against item (5) for "37-Pandori Ram Singh" read "37-Pandori Ran Singh"; and

(ii) at the end of the Notification, the number of the notification may be read as "282/1/PB/78".

[No. 282/1/PB/78/352]

K. GANESAN, Under Secy. (Legal)

आदेश

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1979

का०आ० 831.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 280—खम्माम निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रमैयाह, केथीनेनी, निवासी-म०नं० 1-5-134/1, मयूरी केफे लेन, खम्माम (आन्ध्र प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रमैयाह केथीनेनी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० आ० प्र०-वि०स०/280/78(4)]

ORDERS

New Delhi, the 24th January 1979

S.O. 831.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ramaiah Kethineni, resident of H.no. 1-5-134/1, opposite to Mayuri Cafe Lane, Khammam (Andhra Pradesh), a contesting candidate for general election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in February, 1978 from 280-Khammam costituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules, made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Eelection Commission hereby declares the said Shri Ramaiah Kethineni to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-LA/280/78(4)]

का०आ० 832.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 30-वोर्ली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार डा० दिघे हनुमन्त बाल्याराम, न्यू इरानी चावल, कमरा नं० 26/2, गोखले रोड (दक्षिण) बम्बई-400025 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री डा० दिघे हनुमन्त बालीराम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा०वि०स०/30/78 (75)]

S.O. 832.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Dr. Dighe Hanumant Baliram, New Irani Chawl, Room No. 26/2, Gokhale Road (South), Bombay-400025, Maharashtra a contesting candidate for General Election to the Maharashtra Legislative Assembly held in February, 1978 from 30-Worli constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Dr. Dighe Hanumant Baliram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/30/78 (75)]

का०आ० 833.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 30 वोर्ली निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सैयद नयामतुल्ला अमनातुल्ला, पांडुरंग बुधकर मार्ग, 23-उद्योग नगर, बम्बई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सैयद नयामतुल्ला अमनातुल्ला को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा०वि०स०/30/78 (76)]

S.O. 833.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sayed Nyamtulla Amanatulla, Pandurang Budhkar Marg, 23-Udyog Nagar, Bombay a contesting candidate for General Election to the Maharashtra Legislative Assembly held in February, 1978 from 30-Worli constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sayed Nyamtulla Amanatulla to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislatice Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/30/78 (76)]

का०आ० 834.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 170-नांदेड निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री काले भीमराव गणपतराव, किशनसिंह हाउस, गुरूद्वारा चौरस्ता, जिला नांदेड, नांदेड महाराष्ट्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री काले भीमराव गणपतराव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा०वि०स०/170/78(77)]

S.O. 834.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kale Bhimrao Ganpatrao, Kishansing House Gurudwara Chourasta, Nanded District, Nanded, (Maharashtra) a contesting candidate for General Election to the Maharashtra Legislative Assembly held in February, 1978 from 170-Nanded constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the falure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kale Bhimrao Ganpatrao to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/170/78 (77)]

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1979

का०आ० 835.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 203-अहमदपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शेक गुलाम रसून महबूबसाब, डाक० चकुर, अहमदपुर तालुक, महाराष्ट्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शेक गुलाम रसून महबूबसाब को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा०वि०स०/203/78/(80)]

New Delhi, the 29th January, 1979

S.O. 835.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shaik Gulam Rasoon Mahaboobsab, Post Chakur, Ahmedpur taluk, Maharashtra, a contesting candidate for General Election to the Maharashtra Legislative Assembly held in February, 1978 from 203-Ahmedpur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanaton for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shaik Gulam Rasoon Mahboobsad to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/203/78 (80)]

का० आ० 836.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 203-अहमदपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अरडवाड गोविन्दराव सदाशिव, हिप्परगा के, तालुक-अहमदपुर, महाराष्ट्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है:

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अराडवाड गोविन्दराव सदाशिव को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है

[सं० महा० वि० स०/203/78(81,)]

S.O. 836.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Aradwad Govindrao Sadashiv, Hipparga K, Ahmedpur taluk, (Maharashtra) a contesting candidate for General Election to the Maharashtra Legislative Assembly held in February, 1978 from 203-Ahmedpur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made hereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Aradwad Govindrao Sadashiv to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/203/78 (81)]

का० आ० 837.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 189-सिल्लोड निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री वाघ रंगनाथ मारुती, मुकाम वसाई, डाक० उन्डागांव, सिल्लोद-तालुक, जिला-औरंगाबाद, महाराष्ट्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है :

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री वाघ रंगनाथ मारुती को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा०-वि०सं०/189/78(82)]

S.O. 837.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Wagh Ranganath Maroti, At Wasal, Post Undagaon, Sillod taluka Arungabad District, (Maharashtra) a contesting candidate for General Election to the Maharashtra Legislative Assembly held in February, 1978 from 189-Sillod constituency has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Wagh Ranganath Maroti to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/189/78 (82)]

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1979

का० आ० 838.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 252-कमलापुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कोथा राजी रेड्डी, ग्राम व डाक० वेंकेपल्ली, तालुक-हुजूराबाद, जिला-करीमनगर आन्ध्र प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है :

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कोथा राजी रेड्डी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० आ० प्र०-वि० सं०/252/78(7)]

New Delhi, the 7th February, 1979

S.O. 838.—Whereas the Election Commission is satisfied that Sri Kotha Raji Reddy, Village and P.O. Venkepally, Taluk Huzurabad, District Karimnagar (Andhra Pradesh), a contesting candidate for general election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in February, 1978 from 252-Kamalapur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kotha Raji Reddy to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-LA/252/78(7)]

का० आ० 839.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 208-सनाथनगर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सरीकोन्डा चन्दर राजू, म० नं० 2—95, डाक० मुनी गाडपा, गजवेल तालुक, जिला-मेडाक (आन्ध्र प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सरीकोन्डा चन्दर राजू को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० आ० प्र०-वि० सं०/208/78(8)]

S.O. 839.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sarikonda Chender Raju, H No. 2-95, P.O. Munigadpa, Gajwel Taluk, Medak District (Andhra Pradesh), a contesting candidate for general election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in February, 1978 from 208-Sanathnagar constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sarikonda Chander Raju to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-LA/208/78(8)]

का० आ० 840 :—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 239-मुधोले निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री थोटावारु नरसय्या, निवासी—म० सं० 2—4, निघवा, तालुक मुधोले जिला—आदिलाबाद महाराष्ट्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है:

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री थोटावारु नरसय्या को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० आ० प्र०-वि० स०/239/78(9)]

S.O. 840.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Thotawaru Narsayya, resident of H. No. 2-4, Nighwa, Taluk Mudhole, District Adilabad (Andhra Pradesh), a contesting candidate for general election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in February, 1978 from 239-Mudhole constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declare the said Shri Thotawaru Narsayya to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-LA/239/78(9)]

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1979

का० आ० 841.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उड़ीसा विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 66-भन्जनगर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री दन्डापनी नायक, ग्राम व डाक० तिलसिंगी, जिला गंजम (उड़ीसा) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारणय या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क, के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री दन्डापनी नायक को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० 76/उड़ीसा-वि० स०/66/77]

New Delhi, the 13th February, 1979

S.O. 841.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Dandapani Naik, Village/P.O. Tilsingi, District-Ganjam (Orissa) a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in June, 1977 from 66-Bhanjanagar constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for his failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Dandapani Naik to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/OR-LA/66/77]

का० आ० 842.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 में हुए केरल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 86-पीरमेड निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अननदान, उप-प्रधान, पीरमेड पंचायत, पम्पानार डाक०, जिला-इडुक्की (केरल राज्य) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क, के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री एस० के० अननदान को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० केरल-वि० स०/86/77]

S.O. 842.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri S. K. Anandan, Vice-President, Peermade Panchayat, Pampanar P.O., Idukki District (Kerala State), a contesting candidate for general election to the Kerala Legislative Assembly held in March, 1977 from 86-Peermade constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in puruance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declare the said Shri S. K. Anandan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KL-LA/86/77]

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1979

का० आ० 843.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उड़ीसा विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 127-बारगढ़ निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बिरान्ची नरायण बार्ह, मुकाम छालुकुन्मुन्डा (नुमानपाली) डाक० कुचेडेगा, पु० स्टे० भेदेन, जिला-सम्बलपुर (उड़ीसा) लोक

प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बिरान्ची नरायण भोई को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० 76/उड़ीसा-वि० स०/127/77]

New Delhi, the 14th February, 1979

S.O. 843.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Biranchi Narayan Bhoi, At. Chhalukulunda (Nuanpali) P.O. Kubedega, P.S. Bheden, District Sambalpur (Orissa) a contesting candidate for general election to the Orissa Legislative Assembly held in June, 1977 from 127-Bargarh constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Biranchi Narayan Bhoi to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/OR-LA/127/77]

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1979

का० आ० 844.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 146-गोंडिया निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री तुरकर भैया लाल टीकाराम, अम्बेडकर, वार्ड नं० 33, गोंडिया (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री तुरकर भैया लाल टीकाराम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा०-वि० स०/146/78(98)]

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

New Delhi, the 15th February, 1979

S.O. 844.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Turkar Bhaiyalal Tikaram, Ambedkar Ward No. 33, Gondia Maharashtra, a contesting candidate for General Election to the Maharashtra Legislative Assembly held in February, 1978 from 146-Gondia constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Turkar Bhaiyalal Tikaram to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/146/78(98)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1979

नोटिस

का०आ० 845.—इसके द्वारा लेख्य प्रमाणक नियम (नोटेरीज रूल्स) 1956 के नियम, 6 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है, कि उक्त प्राधिकारी को गुलाम ताहिर, अधिवक्ता, वाराणसी ने उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन, वाराणसी डीवीजन में लेख्य प्रमाणक (नोटेरी का काम करने की नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र भेजा है ।

उक्त व्यक्ति को लेख्य, प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई आपत्तियां हों तो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के चौदह दिन के अन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिख कर भेज दिये जाये।

[संख्या फा. 22/17/79-न्याय]

स० प० हिन्दी, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

New Delhi, the 16th February, 1979

NOTICE

S.O. 845.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Ghulam Tahir, Advocate, Varanasi (Uttar Pradesh) for appointment as a Notary to practice in Varanasi Division.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 22/17/79-Jus.]

L. D. HINDI, Competent Authority

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1979

का०आ० 846.— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय वक्फ परिषद् नियम, 1965 के नियम 4 के साथ पठित वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29) की धारा 8क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री ए० के० हाफिज्का, मीर इकबाल हुसैन और ए० एम० अल्ला पिचई के

त्यागपत्र के कारण हुई रिक्तियों में क्रमशः निम्नलिखित व्यक्तियों को केन्द्रीय वक्फ परिषद् के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है,—

(1) श्री मौलाना सैय्यद अब्दुल हई;

(2) श्री मोईनुद्दीन हैरिस; और

(3) श्री अरिफ बेग, वाणिज्य, नागर पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री और भारत सरकार के विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 673 (ई०), तारीख 22 नवम्बर, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) मद 4 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"4 श्री मौलाना सैय्यद अब्दुल हई,

27, 36वां क्रास, 9वीं मेन रोड, वी ब्लाक, जयनगर, बंगलौर 1"

(ख) मद 15 और 16 के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"15. श्री मोईनुद्दीन हैस्सि, पाटनवाला महल, पाटनवाला रोड, मुम्बई।

16. श्री अरिफ बेग, वाणिज्य, नागर पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।"

[सं० 8(15)/74-वक्फ]

एस० रमय्या, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

(Legislative Department)

New Delhi, the 21st February, 1979

S.O. 846.—In exercise of the powers conferred by section 8A of the Wakf Act, 1954 (29 of 1954), read with rule 4 of the Central Wakf Council Rules, 1965, the Central Government hereby appoints as members of the Central Wakf Council,

(i) Shri Moulana Syed Abdul Hye;

(ii) Shri Moinuddin Harris; and

(iii) Shri Arif Baig, Minister of State in the Ministry of Commerce Civil Supplies and Co-operation;

in the vacancies caused by the resignations of Sarvashri A. K. Hafizka, Mir Iqbal Husain and A. M. Alla Pichai respectively, and makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) No. S.O. 673(E), dated the 22nd November, 1975, namely :—

In the said notification,—

(a) for item 4, the following item shall be substituted, namely :—

"4. Shri Moulana Syed Abdul Hai, 27, 36th Cross, 9th Main Road, V Block, Jayanagar, Bangalore.";

(b) for items 15 and 16, the following items shall be substituted, namely :—

"15. Shri Monuddin Harris,
Patanwala Road,
Paranwala Road,
BOMBAY.

16. Shri Arif Baig, Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation, New Delhi".

[No. 8(15)/74-Wakf]
S. RAMAIAH, Jt. Secy. & Legislative Council

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1978

[आय-कर

का०आ० 847 : राजस्व विभाग, अधिसूचना सं० 46(फा०सं० 203/1/70 आ० क० अ० II), तारीख 6 अप्रैल, 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है,—

संस्था का नाम अर्थात् एम० विश्वेश्वरैया औद्योगिक अनुसंधान और विकास केन्द्र, मुम्बई के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए।

"यह अधिसूचना 31 मार्च, 1981 तक ही विधिमान्य रहेगी।

[सं० 2605 (फा० सं० 203/176/78-आ०क०अ० II)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CORRIGENDUM

New Dehi, the 8th December, 1978

INCOME-TAX

S.O. 847.—The Department of Revenue hereby amend the Notification No. 1416 (F. No. 203/1/70-ITA. II) dated the 6th April, 1970 as under :—

After the name of the Institution i.e. M. Visvesvaraya Industrial Research and Development Centre, Bombay, the following may be added :—

"This notification will be valid upto 31st March, 1981, only".

[No. 2605 (F. 6o. 203/176/78-ITA. II)]

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1978

का० आ० 848 : सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(4) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (2क) के प्रयोजनों के लिए नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमोदित किया है :

वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम का नाम	एक कि० ग्रा० के मापमान पर कुष्ट रोधी औषधि पर क्लोफाजिमिन (लैम्प्रिन) के लिए प्रक्रिया का विकास)।
प्रायोजक का नाम :	आर० डी० एल० केमिकल्स लि०, पोस्ट बाक्स सं० नं 1, सनतनगर (आई० ई०) पी० ओ० हैदराबाद।
कार्यरूप देने के लिए प्रयोगशाला	केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
आरम्भ होने की प्रस्थापित तारीख	4-5-1978
पूर्ण होने की अनुमानित तारीख	3-5-1979
अनुमानित लागत	50,000 रु०

2. केन्द्रीय औषधि अनुसन्धान संस्थान, लखनऊ, के०वै० अ० सं० (सी० एस० आई० आर०) की, जो आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 10(2)(13) के अधीन अनुमोदित है, एक इकाई है ।

[सं० 2609 (फा० सं० 203/127/78-आई० टी०ए II)]

New Delhi, the 12th December, 1978

S.O. 848—It is hereby notified for general information that the following scientific research programme has been approved for the period specified below for the purposes of sub-section (2 A) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, read with Rule 6 (iv) of the I.T. Rules, 1962, by the Secretary, Department of Science & Technology, New Delhi.

Name of the Scientific research programme	Development of Process for Clofazimine (Lamprene) on anti-leprosy drug on 1 Kg. scale.
Name of the sponsorer	IDL Chemicals Ltd., P. Box No.1, Sanatnagar (IE) P.O. Hyderabad.
Implementing Lab	Central Drug Research Institute, Lucknow.
Proposed date of commencement	4.5.1978
Anticipated date of completion.	3.5.1979.
Estimated outlay	Rs. 50,000/-.

2. The Central Drug Research Institute, Lucknow is a unit of CSIR which stands approved u/s. 10(2) (xiii) of the Income-tax Act, 1922.

[No. 2609 (F. No. 203/127/78-ITA II).]

का०आ० 849 : सर्वसाधारण की जानकारी, के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय चिकित्सा अनुसंधान, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(2) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (2) के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात्:—

(1) यह कि संस्था, चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक हिसाब रखेगी।

(2) यह कि संस्था, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की एक वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं ।

संस्था

आई रिसर्च सेन्टर, मद्रास

यह अधिसूचना 23 नवम्बर, 1978 से 22 नवम्बर, 1980 तक की 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

[सं० 2610 (फा० सं० 203/124/78 आ० टी०ए० II)]

S.O. 849.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6(ii) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of "Scientific Research Association" in the field of Medical Research, subject to the following conditions :—

1. That the institution will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of medical research.

2. That the institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Council for each financial year by 31st May, each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

INSTITUTION

Eye Research Centre, Madras

This notification is effective for a period of 2 years from 23 November, 1978 to 22nd November, 1980.

[No. 2610 (F. No. 203/124/78-ITA. II)]

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1978

का०आ० 850 : इस विभाग की अधिसूचना सं० 1347, तारीख 5-6-1976 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(2) के साथ पठित आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (2) के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात्:—

(1) यह कि संस्था, चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक हिसाब रखेगी।

(2) यह कि संस्था, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की एक वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं।

संस्था

बड़ौदा कैंसर खोज केन्द्र, बड़ौदा

यह अधिसूचना 5-6-1978 से 4-6-1980 तक की दो वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी होगी ।

[सं० 2620 (फा० सं० 203/162/78-आईटी ए II)]

New Delhi, the 22nd December, 1978

S.O. 850.—In continuation of this Department's notification No. 1347, dated 5-6-1976, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of Sub-section (I) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6(ii) of the Income-tax Rules 1962 under the category of "Scientific Research Association" in the field of Medical Research, subject to the following conditions :—

1. That the institution will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of medical research.

2. That the institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Council for each

financial year by 31st May each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

INSTITUTION

Baroda Cancer Detection Centre, Baroda

This notification is effective for a period of 2 years from 5-6-1978 to 4-6-1980.

[No. 2620/F. No. 203/162/78-ITA II]

का०आ० 851.—पर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(iv) के साथ पठित आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (2क) के प्रयोजनों के लिए नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमोदित किया है :

वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम का नाम आयोजन कर्ता	प्राइमाक्विन के लिए प्रक्रिया का विकास आई डी एल केमिकल्स लि०, पो०बा० नं० 1, सनतनगर (आई ई), डाक घर हैदराबाद-500018 (आन्ध्र प्रदेश) ।
क्रियान्वित करने वाली प्रयोगशाला	केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ-226001 ।
आरम्भ होने की तारीख	4-5-1978
पूर्ण होने की अनुमानित तारीख	3-5-1979
अनुमानित लागत	85,000 रु०

2. केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के० वै० अ० सं० (सी०एस०आई०आर०) की एक इकाई है, जो आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 10(2)(13) के अधीन अनुमोदित है।

[सं० 2616/फा०सं० 203/173/78-आय०क०अ०II]

S.O. 851.—*It is hereby notified for general information* that the following scientific research programme has been approved for the period specified below for the purposes of sub-section (2A) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6(iv) of the Income-tax Rules, 1962, by the Secretary, Department of Science and Technology, New Delhi.

Name of the Scientific research programme	:	Development of a process for Primaquine.
Name of the sponsorer	:	IDI Chemical Ltd., P.B.No. 1, Sanatnagar (IE), P. O. Hyderabad-500018 (A.P.).
Implementing Lab	:	Central Drug Research Institute, Lucknow-226001.
Date of Commencement	:	4-5-1978.
Anticipated Date of completion	:	3-5-79.
Estimated outlay	:	Rs. 85,000

2. The Central Drug Research Institute, Lucknow is a unit of C.S.I.R. which stands approved u/s. IG(2)(xiii) of the Income-tax, Act, 1922.

[No. 2616/F No. 203/173/78-ITA. II]

का०आ० 852.—पर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने आयकर नियम, 1962 के नियम 6(iv) के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (2क) के प्रयोजनों के लिए नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमोदित किया है ।

वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम का नाम	संचरण लाइन विद्युत रोधकों में औद्योगिक और लवणीय समस्याओं के लिए उपचारी उपाय ।
प्रायोजक का नाम	मैसर्स डब्ल्यू०एस० इंसुलेटर्स आफ इण्डिया लिमिटेड, मद्रास ।
प्रायोजन का स्थान	आई०आई० टी०, मद्रास
आरम्भ होने की प्रस्तावित तारीख	1-11-1978
पूर्ण होने की प्रस्तावित तारीख	31-10-1980
अनुमानित लागत	1,00,000 रु०

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (i) (ii) के अधीन वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 266 तारीख 31 जनवरी, 1961 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है ।

[सं० 2617/फा०सं० 203/174/78-आई टी ए-II)]

S.O. 852.—It is hereby notified for general information that the following scientific research programme has been approved for the period specified below for the purposes of sub-section (2A) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 (iv) of the Income-tax Rules, 1962, by the Secretary, Department of Science & Technology, New Delhi.

Name of the Scientific Research Programme	Remedial Measure for Industrial and Saline Problems in Transmission Line Insulators.
Name of the sponsorer	M/s. W.S. Insulators of India Ltd., Madras.
Sponsored at	I.I.T., Madras.
Proposed date of Commencement	1.11.1978.
Proposed date of Completion	31.10.1980.
Estimated Outlay	Rs. 1,00,000.

2. The Indian Institute of Technology, Madras Stands approved u/s. 35 (i) (ii) of the Income-tax Act, 1961 vide Ministry of Finance Notification No. S.O. 266 dated 31st January, 1961.

[No. 2617/F. No. 203/174/78-ITA.II]

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1978

का०आ० 853.— इस विभाग की अधिसूचना सं० 1250, तारीख 8 मार्च, 1976 (फा०सं० 203/27/76-आ०क०अ०-II) के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (2क) के प्रयोजनों के लिए नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमोदित किया है :—

विनिर्दिष्ट अनुसंधान कार्यक्रम का नाम	शारीरिक बाधाग्रस्त भारतीय ग्रामीण बच्चों के, विशिष्टतः उनके पर्यावरण संबंधी दशाओं के संदर्भ में, पुनर्वास के लिए नवीनतर पद्धतियों का विकास और अनुसंधान तथा ग्रामीण पोलियो-मेरुरज्जुशोथ और प्रमस्तिष्क घात से पीड़ित व्यक्तियों के स्वास्थ्य लाभ के लिए पुनर्वास कम्प्लेक्स में, उनके निवास स्थान पर ही, गूढ़ अध्ययन ।

आयोजन कर्ता	1. अग्रवाल इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, कल्याण भवन, पांचवी मंजिल, 35, कालबा देवी रोड, मुम्बई-2 2. ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी, मर्केंटाइल बैंक बिल्डिंग, फ्लोरा फाउंटेन, फोर्ट, मुम्बई-1 3. बजाज टेम्पो लि०, अकुर्दी, पुणे-29 4. बजाज आटो लि०, अकुर्दी, पुणे-29 5. पी०टी०सी० संघवी एण्ड कं०, 110, शिवाजी नगर, पुणे-5 6. कामधेनु केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज कृषि भवन, 1379, भवानी पेंठ, पुणे-2
आयोजन का स्थान	हस्तीमल संचेती मेमोरियल ट्रस्ट, पुणे ।
परियोजना पर कुल खर्च	93,73,200 रुपए ।
अवधि	1 जनवरी, 1976 से 31 दिसम्बर 1981 तक, पांच वर्ष ।

हस्तीमल संचेती मेमोरियल ट्रस्ट, पुणे को जहां उपरोक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) (ii) के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना सं० 1164 (फा०सं० 203/31/76, आ०क०अ० 11) तारीख 15 दिसम्बर, 1975 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है ।

[सं० 2624/फा०सं० 203/181/78-आय० क० अ०II]

New Delhi, the 30th December, 1978

S.O. 853:—In continuation of this Department's Notification No. 1250 dated 8th March, 1976 (F. No. 203/27/76-ITA.II) it is hereby notified for general information that the following scientific research programme has been approved for the period specified below for the purposes of sub-section (7A) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 by the Indian Council of Medical Research, New Delhi.

1. Name of the Specific Research Programme	"Development and research on Newer methods for rehabilitating rural physically handicapped Indian Children with special reference to their environmental conditions, and an indepth study of rehabilitation of polimyelities and cerebral palsy cases at domiciliary level in a Rural Rehabilitation complex.
2. Sponsored by :	1. Agarwal Engineering Corporation, Kalyan Bhavan, 4th Floor, 35, Kalbadevi Raod, Bombay-2. 2. Great Eastern Shipping Company. Mercantile Bark Building, Flora Fountain, Fort, Bombay-1. 3. Bajaj Tempo Limited, Akurdi, Poona-29. 4. Bajaj Auto Ltd., Akurdi Poona-29 5. P.T.C. Sanghvi & Co., 110, Shivjinagar, Poora-5. 6. Kamdhenu Chemical and Fertilizer, Industries, Krishi Bhavan, 1379, Bhawani Peth, Poona-2.
3. Sponsored at	Hastimal Sancheti Memorial Trust, Pune.
4. Total cost of the Project :	Rs. 93,73,200
5. Duration.	Five years from Ist January, 1976 to 31st December,1978.

2. Hastimal Sancheti Memorial Trust, Poona, where the above programme has been sponsored , has been approved for the purpose of Section 35 (1) (ii) by Notification No. 1164 (F. No. 203/31/76-ITA.II) dated 15th December, 1975.

[No. 2624/F. No. 203/181/78-ITA.II]

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1979

का०आ० 854.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को, आय-कर अधिनियम, 1962 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि संस्था, चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक हिसाब रखेगी ।

(ii) यह कि संस्था, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की एक वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए ।

संस्था

विक्टोरिया अस्पताल, दिचपल्ली, निजामाबाद जिला, आन्ध्र प्रदेश । यह अधिसूचना 18 सितम्बर, 1978 से 17 सितम्बर, 1980 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी ।

[सं० 2648/फा०सं० 203/163/78-आई०टी०ए०-II]

पी० एन० शिंगन, अवर सचिव

New Delhi, the 9th January, 1979

S.O. 854.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, New Delhi the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Rules, 1962 under the category of "Scientific Research Association" in the field of Medical Research, subject to the following conditions :—

(1) That the institution will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of medical research.

(2) That the institution will furnish annual return of its scientific research activities to the Council for each financial year by 31st May each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

INSTITUTION

The victoria Hospital, Dichpalli, Nizamabad Distt, Andhra Pradesh.

This notification is effective for a period of 2 years from 18th September, 1978 to 17th September, 1980.

[No. 2648/F. No. 203/163/78-ITA. II]
P. N. JHINGON, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1978

आय-कर

का०आ० 855—. केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी अधिसूचना सं० 2534 (फा०सं० 197/26/78-आ०क० (ए 1), तारीख 4-9-1978 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

"तारीख 4 सितम्बर, 1978" के स्थान पर
"तारीख 4 अक्तूबर, 1978" पढ़ें ।

[सं० 2613/फा०सं० 197/26/78 आ०क०ए-1]
एम० शास्त्री, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th December, 1978

INCOME-TAX

S.O. 855.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby amends its Notification No. 2534 [F. No. 197/26/78-IT (AI)] dated 4-9-78 as follows :—

For "Dated the 4th September 1978"
Read "Dated the 4th October, 1978."

[No. 2613/F. No. 197/26/78-IT (AI)]
M. SHASTRI, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1979

का०आ० 856—. केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, "श्री मज्जैनी सद्धर्मा सिंहासन श्री तरलाबालू जगद्गुरु ब्रहनमठ, श्री पालकुरीके, सिरिगेरे, वस्त्वया" को निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 2664/फा०सं० 197/124/78-आ०क० (ए-1)]

New Delhi, the 15th January, 1979

S.O. 856.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Madujjaini Saddharma Simhasana Sri Taralabalu Jagadguru Bruhanmath, Sri Palkurike Sirigere Vastavya" for the purpose of the said section for and from the assessment year(s) 1973-74.

[No. 2664/F. No. 197/124/78-IT (AI)]

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1979

का०आ० 857.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "कैथोलिक चर्च, कोठ" को निर्धारण वर्ष 1978-79 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 2702/फा०सं० 197/131/78-आ०क० (ए-1)]

New Delhi, the 31st January, 1979

S.O. 857.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Catholic Church, Koth" for the purpose of the said section for and from the assessment year(s) 1978-79.

[No. 2702/F. No. 197/131/78-IT (AI)]

का०आ० 858.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "मिशनरी इवानगेलिस्म सोसाइटी, कोहलापुर" को निर्धारण वर्ष 1972-73 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 2703/फा० सं० 197/157/78-आ० क० (ए०-1)]
जे० पी० शर्मा, निदेशक

S.O. 858.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notified "Missionary Evangelism Society, Kohlapur" for the purpose" of the said section for and from the assessment year(s) 1972-73.

[No. 2703/F. No. 197/157/78-IT (AI)]
J. P. SHARMA, Director

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1979

स्टाम्प

का०आ० 859.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (i) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा, प्रोमिसरी नोटों के रूप में जारी किए गए, 121 करोड़ रुपये मूल्य के बंधपत्रों पर, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य हैं ।

[सं० 8/79-स्टाम्प—फा०सं० 33/7/79-बिक्री कर]

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 24th February, 1979

STAMPS

S.O. 859.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the form of promissory notes to the value of 121 crores of rupees, floated by the Industrial Development Bank of India are chargeable under this said Act.

[No. 8/79-Stamps—F. No. 33/7/79-ST]

का०आ० 860.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (i) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो दि इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा जनवरी, 1979 में, प्रोमिसरी नोटों के रूप में जारी किए गए, 25 करोड़, 2 लाख और 50 हजार रुपए मूल्य के बंधपत्रों पर, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है ।

[सं० 9/79-स्टाम्प—फा०सं० 33/10/79-बिक्री कर]

S.O. 860.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the form of promissory notes to the value of twenty-five Crores, two lakhs and fifty thousands of rupees issued in January, 1979 by the Industrial Credit and Investment Corporation of India, are chargeable under the said Act.

[No. 9/79-Stamps—F. No. 33/10/79-ST.]

का०आ० 861.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 2 सितम्बर, 1978 के भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में पृष्ठ 2339 पर प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के दिनांक 26 अगस्त 1978 के का०आ०सं० 2483 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है, जो जम्मू तथा काश्मीर राज्य वित्तीय निगम द्वारा वचन पत्रों के रूप में जारी किये गये छप्पन लाख रुपये मूल्य के बन्ध पत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है।

[सं० 10/79-स्टाम्प-फा०सं० 33/40/78-बिक्री कर]

एस० डी० रामस्वामी, अवर सचिव

S.O. 861.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), S.O. No. 2483, dated 26th August, 1978, published at page 2339 of the Gazette of India Part II, section 3, Sub-section (ii) dated the 2nd September, 1978, the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the form of promissory notes to the value of fifty six lakhs of rupees, issued by the Jammu and Kashmir State Financial Corporation, are chargeable under the said Act.

[No. 10/79-Stamps-F. No. 33/40/78-ST.]

S. D. RAMASWAMY, Under Secy.

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1979

का०आ० 862.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिसके कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

1. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली।
3. महालेखाकार, वाणिज्य निर्माण कार्य एवं विविध, नई दिल्ली।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. महालेखाकार-I, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. महालेखाकार-II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. महालेखाकार-III, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8. महालेखाकार-II, मध्य प्रदेश (भोपाल शाखा सहित) ग्वालियर।
9. महालेखाकार-बिहार, I राँची।
10. मुख्य लेखा परीक्षक, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली।
11. मुख्य लेखा परीक्षक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
12. मुख्य लेखा परीक्षक, डाक-तार, दिल्ली।
13. डाक-तार, लेखा परीक्षा कार्यालय, भोपाल।
14. निदेशक, भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टाफ कालिज, शिमला।
15. सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड एवं पदेन निदेशक वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा, नई दिल्ली।
16. सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड एवं पदेन निदेशक वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा, देहरादून।
17. सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड एवं पदेन निदेशक वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा, राँची।
18. निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली।
19. वरिष्ठ उप निदेशक, लेखा परीक्षा रक्षा सेवाएं, मध्य कमान, मेरठ।
20. वरिष्ठ उप निदेशक, लेखापरीक्षा रक्षा सेवाएं, पश्चिम कमान, मेरठ।
21. वरिष्ठ उप निदेशक, लेखापरीक्षा रक्षा सेवाएं, देहरादून।
22. वरिष्ठ उप निदेशक, लेखापरीक्षा रक्षा सेवाएं, पटना।
23. लेखा परीक्षा अधिकारी, रक्षा सेवाएं, इलाहाबाद।
24. लेखापरीक्षा अधिकारी, रक्षा सेवाएं, दिल्ली कैण्ट।
25. वरिष्ठ उप मुख्य लेखापरीक्षक (आयुक्त निर्माणी) कानपुर।

[सं० ए-11019/1/78-ई०जी० 1]

सरोज कुमार दास, अवर सचिव

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 3rd January, 1979

S.O. 862.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (use for the official purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following offices of the IA&AD, the Staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. Comptroller & Auditor General of India, New Delhi.
2. Accountant General Central Revenue, New Delhi.
3. Accountant General Commerce Works & Misc., New Delhi.
4. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
5. Accountant General-I, Uttar Pradesh, Allahabad.
6. Accountant General-II, Uttar Pradesh, Allahabad.
7. Accountant General-III, Uttar Pradesh, Allahabad.
8. Accountant General-II, Madhya Pradesh (including Bhopal Branch), Gwalior.
9. Accountant General-I, Bihar, Ranchi.
10. Chief Auditor, Northern Railway, New Delhi.
11. Chief Auditor, North Eastern Railway, Gorakhpur.
12. Chief Auditor, Posts & Telegraph, Delhi.
13. Posts & Telegraph Audit Office, Bhopal.
14. Director, Indian Audit & Accounts Services Staff College, Simla.
15. Member, Audit Board & Ex-officio, Director of Commercial Audit, New Delhi.
16. Member, Audit Board & Ex-officio, Director of Commercial Audit, Dehradun.
17. Member, Audit Board & Ex-officio, Director of Commercial Audit, Ranchi.
18. Director of Audit Defence Services, New Delhi.
19. Senior Deputy Director of Audit Defence Services (Central Command), Meerut.

20. Sr. Deputy Director of Audit Defence Services (Western Command), Meerut.

21. Sr. Deputy Director of Audit Defence Services, Dehradun.

22 Senior Deputy Director of Audit Defence Services, Patna.

23. Audit Officer, Defence Services, Allahabad.

24. Audit Officer, Defence Services, Delhi Cantt.

25. Sr. Dy. Chief Auditor (Ordnance Factories), Kanpur.

[No. A-11019/1/78-EGL]

S. K. DAS, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

बीमा प्रभाग

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1979

का०आ० 863 जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री ए०एस० गुप्ता को भारतीय जीवन बीमा निगम के सदस्य नियुक्त करती है।

[फा०संख्या 124(1) बीमा 4/79]

(Department of Economic Affairs)

(Insurance Division)

New Delhi, the 23rd February, 1979

S.O. 863.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri A. S. Gupta, as Member of the Board of Life Insurance Corporation of India.

[F. No. 124(1)Ins. IV/79]

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1979

शुद्धि पत्र

का०आ० 864 दिनांक 28 दिसम्बर, 1978 की इस विभाग की अधिसूचना में उल्लिखित शब्द 'निदेशक' के स्थान पर 'सदस्य' पढ़िए।

[फाइल संख्या 81(1) बीमा-4/78]

शिव दयाल रहेजा, अवर सचिव

New Delhi, the 24th February, 1979

CORRIGENDUM

S.O. 864.—For the word "Director" mentioned in this Department's Notification dated the 28th December, 1978 read as "Member".

[F. No. 81(1)Ins. IV/78]
S. D. RAHEJA, Under Secy.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1979

का०आ० 865 निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि प्रसाधन के लिए साबुन के निर्यात से पूर्व निरीक्षण किया जाए।

केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव तैयार किए हैं तथा उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (28) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है।

अतः अब, उक्त उप-नियम के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्तावों को उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है।

2. यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे में यदि कोई व्यक्ति कोई आपत्ति या सुझाव भेजना चाहता है तो वह उन्हें इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालिस दिनों के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद् 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर' 14/1 बी इजरा स्ट्रीट (आठवीं मंजिल) कलकत्ता-1 को भेज सकता है।

प्रस्ताव

(1) अधिसूचित करना कि प्रसाधन के लिए साबुन निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण के अधीन होंगे।

(2) (क) इस आदेश के उपाबन्ध 1 में प्रसाधन के साबुन के लिए दिए गए विनिर्देशों के प्रसाधन के साबुन के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना, या

(ख) क्रेता तथा निर्यातकर्ता के मध्य हुए करार के अनुसार निर्यात-संविदा में प्रसाधन के साबुन के लिए अनुबंधित विनिर्देशों को मान्यता देना, परन्तु यह तब जब ऐसे विनिर्देश उपाबन्ध 1 के अनुसार मान्य न्यूनतम विनिर्देशों से निम्न न हों।

(3) इस आदेश के उपाबन्ध ii में दिए गए प्रस्ताव के साबुन के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) प्रारूप नियम, 1979 के अनुसार, क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को ऐसे क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना, जो कि ऐसे प्रसाधन के साबुन पर निर्यात से पूर्व लागू होगा।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में ऐसे प्रसाधन के लिए साबुन के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अभिकरण द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाणपत्र न हो कि प्रसाधन के लिए साबुन उक्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है या उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य मोहर या चिन्ह उस पर न लगा हो।

3. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को, प्रसाधन के लिए साबुन (5 किलोग्राम से अनधिक) के नमूनों के भूमि, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा निर्यात को लागू नहीं होगी।

4. इस आदेश में प्रसाधन के लिए साबुन से प्रसाधन का साबुन पूरी तरह साबुनीकृत मशीन से तैयार किया गया या उसके बिना तैयार किया गया या अपारदर्शी या पारदर्शी संमागीकृत सफेद या रंगीन या पारदर्शी साबुन जो सुगन्धित तथा पक्की चिकनी टिक्की के रूप

में तैयार किया गया है, अभिप्रेत है, जिसमें अच्छी सफाई करने तथा झाग देने की विशेषताएं हों। सुगन्ध तथा आर्द्रता तथा वाष्पशील पदार्थ के अतिरिक्त, प्रसाधन के लिए साबुन मे रंजक पदार्थ, परिरक्षक, औषधि अतिवसामय पदार्थ तथा ऐसे अतिरिक्त पदार्थ हो सकते हैं जो लेबल पर घोषित किये गए है। तथापि, सभी पूर्वोक्त पदार्थ जब वे साबुन में मिले हों, प्रयोग में हानि रहित होंगे ।

उपाबन्ध I

[पैरा 2 का उप-पैरा (2) देखिए]

क्रम सं०	विशेषताएं	अपेक्षाएं प्रसाधन के लिए साबुन (अपारदर्शी)	प्रसाधन के लिए साबुन (पारदर्शी)
1.	कुल वसा पदार्थ, संहति के आधार पर न्यूनतम प्रतिशत	76.0	60.0
2.	रोजिन, अम्ल, कुल वसा पदार्थ की संहति के आधार पर अधिकतम प्रतिशत	3.0	15.0
3.	सोडियम क्लोराइड (एन ए सी एल) की तरह कास्टिक अल्कली मुक्त संहति के आधार पर अधिकतम प्रतिशत	0.05	0.05
4.	असाबुनीकृत वसा पदार्थ, संहति के आधार पर अधिकतम प्रतिशत	0.05	..
5.	अल्कोहल में धुलनशील पदसंहति के आधार पर अधिकतम प्रतिशत	2.5	..
6.	आर्द्रता तथा वाष्पशील पदार्थ (105° सी० पर) संहति के आधार पर अधिकतम प्रतिशत	—	20 0
7.	पदार्थ में अधुलनशील पदार्थ, संहति के आधार पर अधिकतम प्रतिशत	—	0.5

उपाबन्ध II

[पैरा 2 का उप-पैरा (3) देखिए]

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अधीन बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का प्रारूप ।

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम, प्रसाधन के लिए साबुन का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1979 है ।

2. परिभाषा:—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन कोचीन, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई तथा दिल्ली में स्थापित अभिकरणों में से कोई अभिकरण अभिप्रेत है;

(ग) प्रसाधन के लिए साबुन से प्रसाधन का अपारदर्शी या पारदर्शी साबुन पूरी तरह साबुनीकृत, मशीन से तैयार किया गया या उसके बिना तैयार किया गया या संमागीकृत सफेद या रंगीन पारदर्शी साबुन, जो सुगन्धित तथा पक्की चिकनी टिक्की के रूप में तैयार किया गया है, अभिप्रेत है, जिसमें अच्छी सफाई करने तथा झाग देने की विशेषताएं हों । सुगंध तथा आर्द्रता तथा वाष्पशील पदार्थ के अतिरिक्त प्रसाधन के लिए साबुन में रंजक पदार्थ परिरक्षम, औषधी, अतिवसामय पदार्थ तथा ऐसे अतिरिक्त पदार्थ हो सकते है, जो कि लेबल पर घोषित किए गए हैं । तथापि सभी पूर्वोक्त पदार्थ जब वे साबुन में मिलें हों, प्रयोग में हानि रहित होंगे ।

3. निरीक्षणक का आधार :—निर्यात के लिए साबुन का निरीक्षण, यह देखने की दृष्टि से किया जाएगा कि प्रसाधन के लिए साबुन, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य विनिर्देशों के अनुरूप है :—

(क) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि, उत्पाद का विनिर्माण उपाबंध III में यथा विनिर्दिष्ट उत्पादन के अनुक्रम में आवश्यक क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करते हुए किया गया है ।

या

(ख) उपबन्ध—IV में विनिर्दिष्ट ढंग के अनुसार निरीक्षण तथा परीक्षण के आधार पर किया जाएगा।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :—(1) प्रसाधन के लिए साबुन के परेषण का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता, निर्यात संविदा या आदेश की एक प्रति के साथ संविदागत विनिर्देशों का ब्यौरा देते हुए अभिकरण को लिखित रूप से सूचना देगा जिससे वह नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर सके।

(2) निर्यात के लिए प्रसाधन के साबुन का निर्माण उपाबन्ध III में अधिकथित उत्पादन के दौरान पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग करते हुए किया गया है तथा यदि इस प्रयोजन के लिए परिषद् द्वारा गठित विशेषज्ञों के पैनल द्वारा विनिर्माता यूनिट के संबंध में यह अधिनिर्णय दिया जा चुका है कि उसमें उत्पादन के दौरान पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण रखने की पर्याप्त व्यवस्था है तो निर्यात कर्ता उप-नियम 2 में उल्लिखित सूचना के साथ एक घोषणा भी देगा कि निर्यात के लिए आशयित प्रसाधन के लिए साबुन का परेषण का विनिर्माण उपाबन्ध III में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करते हुए किया गया है तथा परेषण इस प्रयोजन के लिए मान्य मानक विनिर्देशों के अनुरूप है ।

(3) ऐसी सूचना या घोषणा या दोनों की एक प्रति एक साथ परिषद् के निम्नलिखित कार्यालयों में से किसी एक कार्यालय को जो निरीक्षण के स्थान के निकटतम होगा, भेजी जाएगी अर्थात् :—

प्रधान कार्यालय — निर्यात निरीक्षण परिषद्,
'वर्ल्ड ट्रेड सैन्टर',
14/1-बी एजरा स्ट्रीट (आठवीं मंजिल) कलकत्ता-700001.

क्षेत्रीय कार्यालय — निर्यात निरीक्षण परिषद्,
अमन चैम्बर्स,
113, महर्षि कार्वे रोड,
बम्बई-400004.

निर्यात निरीक्षण परिषद्,
मनोहर बिल्डिंग्स,
महात्मा गांधी रोड,
एर्नाकुलम, कोचीन-682011.

निर्यात निरीक्षण परिषद्,
म्युनिसपल मार्केट बिल्डिंग्स,
3, सरस्वती मार्ग,
करोल बाग,
नई दिल्ली-110005.

(4) निर्यात कर्त्ता अधिकरण को परेषण पर लगाए जाने वाले पहचान चिह्न भी देगा ।

(5) उप-नियम (1) के अन्तर्गत प्रत्येक सूचना तथा उपनियम (2) के अन्तर्गत प्रत्येक घोषणा यदि कोई है विनिर्माता के परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम सात दिन पहले दी जाएगी ।

(6) उप-नियम (1) के अन्तर्गत प्रत्येक सूचना तथा उप-नियम (2) के अन्तर्गत प्रत्येक घोषणा यदि कोई है के प्राप्त होने पर, अधिकरण :—

(क) अपना यह समाधान कर लेने पर कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान विनिर्माता ने उपाबन्ध III में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग किया है तथा इस प्रयोजन के लिए मानक विनिर्देशों के अनुरूप उत्पाद का विनिर्माण करने के संबंध में परिषद् द्वारा जारी किए गए, अनुदेशों का यदि कोई हो, पालन किया है सात दिन के भीतर यह घोषणा करते प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि प्रसाधन के लिए साबुन का परेषण निर्यात योग्य है ? यदि विनिर्माता निर्यात कर्त्ता नहीं है तथापि परेषण का औतिकी रूप से सत्यापन किया जाएगा तथा ऐसे सत्यापन तथा निरीक्षण आवश्यकतानुसार अधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि उपर्युक्त शर्तों का पालन किया गया है । किन्तु अधिकरण तथापि निर्यात के लिए आशयित कुछ परेषणों की तत्काल जांच करेगा ।

(ख) यदि निर्यात कर्त्ता ने उप-नियम (2) के अधीन घोषित नहीं किया है कि उपाबन्ध III में अधिपर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग किया गया है तो अपना यह समाधान कर लेने पर कि प्रसाधन के लिए साबुन का परेषण इस प्रयोजन के लिए मान्य मानक विनिर्देशों के अनुरूप है, उप IV में यथा अधिकथित किए गए निरीक्षण या परीक्षण के आधार पर या दोनों के आधार पर ऐसा निरीक्षण करने से सात दिन के भीतर यह घोषणा करते हुए प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि प्रसाधन के लिए साबुन का परेषण निर्यात योग्य है :

परन्तु जहां अधिकरण का यह समाधान नहीं होता है वहां वह उक्त सात दिन की अवधि के भी निर्यात कर्त्ता को यह घोषणा करते हुए प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार कर देगा कि प्रसाधन के लिए साबुन का परेषण निर्यात योग्य नहीं है तथा ऐसे इंकार की सूचना उसके कारणों सहित निर्यात-कर्त्ता को देगा।

(7) विनिर्माता निर्यातकर्त्ता ही है या उप-नियम (6) (ख) के अधीन परेषण का निरीक्षण किया गया है, या दोनों मामलों में, अधिकरण पैकेजों को परेषण में इस ढंग से यह सुनिश्चित करने के लिए सील बन्द पैकेजों में हस्तक्षेप न की जा सके । परेषण की अस्वीकृति की दशा में, यह निर्यात-कर्त्ता चाहे तो परेषण अधिकरण द्वारा सील बन्द नहीं किया जाएगा किन्तु ऐसी दशा में तथापि निर्यात-कर्त्ता अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील करने का हकदार नहीं होगा ।

मान्यताप्राप्त चिन्ह चिपकाना और उसकी प्रक्रिया :—भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणीकरण चिन्ह) अधिनियम, 1952 (1952 का 36) भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणीकरण चिन्ह) नियम, 1955 तथा भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणीकरण चिन्ह) विनियम, 1955 के उपबन्ध निर्यात के लिए आशयित प्रसाधन के लिए साबुन से संबंधित डिब्बों या पैकेजों पर मान्य चिन्ह या सील के लगाए जाने की प्रक्रिया के संबंध में यथा संभव लागू होंगे ।

6. निरीक्षण स्थान :—इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण किया जाएगा या (क) ऐसे उत्पाद के विनिर्माताओं के परिसर पर या (ख) उन परिसरों में किया जाएगा जहां निर्यातकर्त्ताओं द्वारा माल प्रस्तुत किया गया है परन्तु यह तब इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों ।

7. निरीक्षण फीस :— प्रत्येक परेषण के लिए न्यूनतम 50 रुपये की अधीन रहते हुए, ऐसे प्रत्येक परेषण के लिए पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रत्येक एक सौ रुपये के लिए चालीस पैसे की दर से फीस के रूप में दी जाएगी ।

8. अपील :— (1) नियम 4 के उपनियम (6) के अधीन अधिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर दिए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध अपील उसे ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने से दस दिन के भीतर, इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात व्यक्तियों के विशेषज्ञों के पैनल को कर सकता है ।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता में दो तिहाई सदस्य गैर सरकारी सदस्य होंगे ।

(3) विशेषज्ञों के पैनल की गणपूर्ति तीन से होगी ।

(4) विशेषज्ञों का पैनल अपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर उसे निपटा देगा ।

उपाबन्ध II

[नियम 3(के) देखिए]

क्वालिटी नियंत्रण :

विनिर्माता प्रसाधन के प्रमुख साबुन पर क्वालिटी नियंत्रण, नीचे अधिकथित उत्पादों के विनिर्माण अनुरक्षण और पैक करने के विभिन्न प्रक्रमों पर निम्नलिखित नियंत्रण रखकर तथा इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित नियंत्रण स्तरों के अनुसार सुनिश्चित करेगा, अर्थात् :—

(1) क्रय तथा कच्ची सामग्री नियंत्रण —

(क) विनिर्माता प्रयुक्त की जाने वाली कच्ची सामग्री की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए विनिर्देश अधिकथित करेगा ।

(ख) स्वीकृत परेषणों के साथ या तो क्रय विनिर्देशों की अपेक्षाओं की संपुष्टि करते हुए प्रमाण-कर्ता का परख प्रमाण पत्र या निरीक्षण प्रमाण होगा जिसे दशा में क्रेता द्वारा विशिष्ट प्रदाय-कर्ता के लिए उक्त परख या निरीक्षण प्रमाण पत्र की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए 10 परेषणों में से कम से कम एक परेषण की यदा-कदा जांच की जाएगी । या क्रय की गई सामग्री का या तो कारखाने के अन्दर स्थित प्रयोगशाला में या बाहरी प्रयोगशाला में या परख ग्रह में नियमित रूप से जांच और निरीक्षण किया जाएगा ।

(ग) निरीक्षण या परख के लिए नमूने का लिया जाना अभिलिखित अन्वेषणों पर आधारित होगा ।

(घ) निरीक्षण या परख किए जाने के पश्चात् स्वीकृत तथा अस्वीकृत माल का पृथक् करने तथा अस्वीकृत माल के निपटारे के लिए व्यवस्थित पद्धतियां अपनाई जाएंगी ।

(ङ) उक्त कथित नियंत्रणों के बारे में पर्याप्त अभिलेख विनिर्माता द्वारा तथा व्यवस्थित रूप से रखा जाएगा ।

(2) प्रक्रिया नियंत्रण —

(क) विनिर्माण के विभिन्न प्रक्रमों के लिए विनिर्माता ब्यौरेवार विनिर्देश अधिकथित करेगा ।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देशों में अधिकथित प्रक्रियाओं के नियंत्रण के लिए उपस्कर तथा यंत्र समुच्चय व पर्याप्त सुविधाएं होंगी ।

(ग) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रयोग नियंत्रण के सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माता पर्याप्त अभिलेख रखेगा ।

(3) उत्पाद नियंत्रण--

(क) अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रमान्य विनिर्देशों के अनुरूप उत्पादन की जाच करने के लिए विनिर्माता के पास या तो अपनी परख सुविधाएं होंगी या उसकी पहुंच वहां तक है जहां ऐसी परख सुविधाएं विद्यमान हैं।

(ख) परख तथा निरीक्षण के लिए नमूने का लिया जाना अभिलेखित अन्वेषणों पर आधारित हों।

(ग) नमूने लेने तथा किए गए परीक्षणों के संबंध में पर्याप्त अभिलेख नियमित तथा व्यवस्थित से रखा जाएगा।

(घ) उत्पाद की जांच करने के लिए न्यूनतम नियंत्रण स्तर अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार।

(4) परिरक्षण नियंत्रण—

भंडारकरण तथा अभिवहन दोनों के दौरान उत्पाद को अच्छी तरह परिरक्षित किया जाएगा।

(5) पैकिंग नियंत्रण —

उत्पाद की पैकिंग करने के लिए पैकिंग विनिर्देशों अनुसूची में वर्णित नियंत्रणों को पूरा करते हुए अधिचित किए जाएंगे।

अनुसूची

(1) उत्पादों के लिए नियंत्रण के स्तर

(उपाबंध III का उप-पैरा (iii) (घ) देखिए)

क्र० सं०	विशेषताएं	अपेक्षाएं	परख किए जाने वाले संयुक्त नमूनों की सं०	आवृत्ति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
(1)	कुल वसा पदार्थ संहति के आधार पर न्यूनतम प्रतिशत	मानक विनिर्देशों के अनुसार	1	प्रति बैच	—
(2)	रोजिन अम्ल, कुल वसा पदार्थ की संहति के आधार पर अधिकतम प्रतिशत	—	—	—	—
(3)	सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में कास्टिक अल्कली मुक्त संहति के आधार पर अधिकतम प्रतिशत	—	—	—	—
(4)	असाबुनीकृत वसा पदार्थ, संहति के आधार पर अधिकतम प्रतिशत	—	—	—	जहां भी लागू
(5)	अल्कोहल में अविलेय पदार्थ संहति के आधार पर अधिकतम प्रतिशत	—	—	—	—
(6)	आद्रता तथा वाष्पशील पदार्थ (105° से० पर) संहति के आधार पर अधिकतम प्रतिशत				
(7)	पानी में अविलेय पदार्थ, संहति के आधार पर अधिकतम प्रतिशत	—	—	—	
(8)	अन्य परखें	—	—	यथोक्त	

(2) पैकिंग के लिए नियंत्रण के स्तर

(उपाबंध III का उप-पैरा (5) देखिए)

1. अभिवहन के दौरान उठाई--धराई की दृष्टि से पैकेज या डिब्बे सुडौल और पर्याप्त क्षमता वाले होंगे।

प्रत्येक पैकेज या डिब्बे पर निम्नलिखित उल्लेख होगा, अर्थात :--

(क) सामग्री का नाम

(ख) विनिर्माता का नाम तथा व्यापार चिन्ह, यदि कोई है।

(ग) सामग्री की क्वालिटी

(घ) बैच संख्या।

उपाबन्ध IV

1. परेषणानुसार निरीक्षण :--प्रसाधन के लिए साबुन के परेषण का यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वह अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्य मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

2. नमूने मानदंड के लिए संविदागत विनिर्देशों में विनिर्दिष्ट न होने पर अनुबंध की निम्नलिखित सारणी में दिए गए मानदंड लागू होंगे।

सारणी

नमूने लेने के लिए मापमान

लॉट में पैकेजों की संख्या	यादृच्छिक चुने जाने वाले पैकेजों की संख्या
(1)	(2)
3 तक	2
4 से 15 तक	3
16 से 40 तक	4
41 से 65 तक . . .	5
66 से 110 तक	7
111 से अधिक .	10

टिप्पणी :--एक परेषण में विनिर्माण के उसी बैच से लिए गए एक ही आकार प्रकार वाले प्रसाधन के लिए साबुन के सभी पैकेज एक लॉट का गठन करेंगे।

2. उपर्युक्त रूप में लिए गए पैकेजों में से नमूना लेने के प्रयोजन के लिए यादृच्छिक एक या अधिक डिब्बे लिए जाएंगे।

[सं० 6 (29)/76-नि०नि० तथा नि०उ०]

MINISTRY OF COMMERCE

(Civil Supplies and Co-operation)

ORDER

New Delhi, the 10th March, 1979

S.O. 865.—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India that toilet soaps should be subject to inspection prior to export ;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council, as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964.

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within forty-five days of the date of publication of this order in the official Gazette to the Export Inspection Council, 'World Trade Centre', 14/1B, Ezra Street (7th floor), Calcutta-1.

PROPOSALS

(1) To notify that toilet soaps shall be subject to quality control and inspection prior to export ;

(2) To recognise—

(a) The minimum specifications for toilet soaps as set out at Annexure-I to this order as the standard specifications for toilet soaps ; or

(b) The specifications which may be stipulated for toilet soaps in the export contract as agreed between the buyer and the exporter provided that such specifications do not fall below the recognised minimum specifications as per Annexure-I.

(3) To specify the type of quality control and inspection in accordance with the draft Export of Toilet Soaps (Quality Control and Inspection) Rules, 1979 set out in Annexure-II to this order as the type of Quality Control and Inspection which would be applied to such toilet soaps prior to export ;

(4) To prohibit the export, in the course of international trade of such toilet soaps unless the same is accompanied by a certificate issued by an agency established by the Central Government under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that the toilet soaps conform to the aforesaid standard specifications or affixed with a seal or mark recognised by the Central Government under section 8 of the said Act.

3. Nothing in this order shall apply to the export by land, sea or air of samples of toilet soaps (not exceeding 5 kg.) to the prospective buyer.

4. In this order "toilet soaps" shall mean opaque or transparent toilet soaps, thoroughly saponified, milled or un-milled soap or homogenized soap, white or coloured or transparent perfumed and compressed in the form of firm smooth cakes, and shall possess good cleaning and lathering properties. In addition to perfume and moisture and volatile matter, toilet soaps may contain only colouring matter, preservatives medicaments, superfatting agents and such additional substances as are declared on the level. The transparent toilet soap may contain sugar and glycerol. However, all the foregoing materials shall be non-injurious in use with soap.

ANNEXURE I

(See sub-paragraph (2) of paragraph 2)

Sl. No.	Characteristics	Requirements	
		Toilet soap (opaque)	Toilet soap (Transparent)
1.	Total fatty matter, precent by mass, *Min*	76.00	60.00
2.	Rosin acids, percent by mass of total fatty matters, *Max*	3.0	15.0
3.	Free Caustic alkali, as sodium hydroxide (Nao H) percent by mass *Max*	0.05	0.05
4.	Unsaponified fatty matter, percent by mass, *Max*	0.5	..
5.	Matter insoluble in alcohol percent by mass, *Max*	2.5	..
6.	Moisture and Volatile matter (at 105°C), percent by mass, *Max*	..	20.0
7.	Matter insoluble in water percent by mass, *Max*	..	0.5

ANNEXURE II

(See sub-paragraph (3) of paragraph 2)

Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963)

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Export of Toilet soaps (Quality Control and Inspection) Rules, 1979.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) :

(b) "agency" means any one of the agencies established under section 7 of the Act at Cochin, Madras, Calcutta, Bombay and Delhi ;

(c) "toilet soap" means opaque or transparent toilet soaps, thoroughly saponified, milled or un-milled soap or homogenized soap, white or coloured or transparent, perfumed and compressed in the form of film smooth cakes and shall possess good cleaning and lathering properties. In addition to perfume and moisture and volatile matter, toilet soaps may contain only colouring matter preservatives, medicaments, superfatting agents and such additional substance as are declared on the level. The transparent toilet soap may contain sugar and glycerol. However, all the foregoing materials shall be non-injurious in use with soap.

3. Basis of Inspection.—Inspection of toilet soaps for export shall be carried out with a view to seeing that the toilet soaps conform to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

either

(a) by ensuring that the products have been manufactured by exercising necessary in-process quality control as specified in Annexure-III

or

(b) on the basis of inspection and testing carried out in the manner specified in Annexure-IV.

4. Procedure of Inspection.—(1) An exporter intending to export a consignment of toilet soaps shall give an intimation

in writing to the agency furnishing therein details of the contractual specifications along with a copy of the export contract or order to enable the agency to carry out inspection in accordance with rule 3.

(2) For export of toilet soaps manufactured by exercising adequate in process quality control as laid down in Annexure-III and in the manufacturing unit adjudged as having adequate in-process quality control drills by the Council or panel of experts constituted by the Council for this purpose, the exporter shall also submit along with the intimation mentioned in sub-rule (1) a declaration that the consignment of toilet soaps intented for export has been manufactured by exercising adequate quality control as laid down in Annexure-III and that the consigment conforms to the standard specifications recognised for the purpose.

(3). A copy of each such intimation or declaration or both shall also be simultaneously endorsed to any of the following offices of the Council, which is nearest to the place of inspection namely :—

Head Office	Export Inspection Council, 'World Trade Centre' 14/1B, Ezra Street (7th floor), Calcutta—700001.
Regional Offices	Export Inspection Council Aman Chambers 113, M. Karve Road, Bombay—400004.
	Export Inspection Council, Manohar Buildings, Mahatma Gandhi Road Ernakulam, Cochin—682011
	Export Inspection Council, Municipal Market Building 3, Saraswati Marg, Karol Bagh, New Delhi-110005.

(4) The exporter shall also furnish to the agency the identification marks applied on the consignment.

(5) Every intimation under sub-rule (1) and declaration, if any, under sub-rule (2) above shall be given not less than seven days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises.

(6) On receipt of the intimation under sub-rule (1) and the declaration, if any, under sub-rule (2) the agency—

(a) on satisfying itself that during the process of manufacture, the manufacturer had exercised adequate quality control as laid down in Annexure-III and followed the instructions, if any, issued by the Council in this regard to manufacture the product to conform to the standard specifications recognised for the purpose shall within seven days issue a certificate declaring the consignment of toilet soaps as exportwirthy. In cases where the manufacturer is not the exporter, however, the consigment shall be physically verified and such verification and inspection as necessary shall be carried out by the agency to ensure that the above conditions are complied with. The agency shall, however, conduct spot checks of some of the consignments meant for export.

(b) In cases where the exporter has not declared under sub-rule (2) that adequate quality control as laid down in Annexure-III had been exercised, on satisfying itself that the consigment of toilet soaps conform to the standard specification recognised for the purpose on the basis of inspection or testing carried out as laid down in Annexure-IV or on the basis of both, shall within seven days of carrying out such inspection issue a certificate declaring the consignment of toilet soaps as exportworthy.

Provided that where the agency is not so satisfied it shall within the said period of seven days refuse to issue a certificate to the exporter declaring the consignment of toilet soaps as exportwirthy and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.

(7) In cases where the manufacturer is not the exporter or the consignment is inspected under sub-rule (6) (b), or in both the cases, the agency shall, immediately after completion of the inspection, seal the packages in the consignment in a manner as to ensure that the sealed packages cannot be tampered with. In case of rejection of the consignment if the exporter so desires, the consignment may not be sealed by the agency, but in such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer any appeal against the rejection.

5. Affixation of recognised mark and procedure thereof.—The provisions of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1953 (36 of 1952) the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 and the India Standard Institution (Certification Marks) Regulation, 1955 shall so far as may apply in relation to the procedure of affixation of the recognised mark or seal on cartons or packages relating to the toilet soaps meant for export.

6. Place of Inspection.—Every inspection under these rules shall be carried out either (a) at the premises of the manufacturer of such product or (b) at the premises at which the goods are offered by the exporter provided adequate facilities for the purpose exist therein.

7. Inspection fee.—Subject to minimum of Rs. 50 for each consignment, a fee at the rate of forty paise for every one hundred rupees of the F.O.B. value for each such consignment shall be paid as inspection fee.

8. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (6) of rule 4, may within ten days of the receipt of communication of such refusal by him prefer an appeal to such panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons as may be constituted by the Central Government for the purpose.

(2) The panel of experts shall consist of at least two-thirds of non-official of the total membership of the panel of experts.

(3) The quorum for the panel of experts shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of by the panel of experts within fifteen days of its receipt.

ANNEXURE III

[See under rule 3 (a)]

Quality Control

The quality control of toilet soaps shall be ensured by the manufacturer by effecting the following controls at different stages of manufacture, preservation and packing of the products as laid down below together with the levels of control as set out in the schedule appended hereto.

(i) Purchase and raw material control—

(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of raw materials to be used.

(b) Either the accepted consignments shall be accompanied by a supplier's test and inspection certificate corroborating the requirements of the purchase specifications, in which case occasional checks shall be conducted at least once in 10 consignments by the purchaser for a particular supplier to verify the correctness of the aforesaid test or inspection certificate or the purchased material shall be regularly tested and inspected either in the laboratory within the factory or in an outside laboratory or test house.

(c) The sampling for inspection or test to be carried out shall be based on the recorded investigations.

(d) After the inspection or test is carried out, systematic methods shall be adopted in segragating the accepted and rejected materials and for disposal of the rejected materials.

(e) Adequate records in respect of the aforesaid controls shall be regularly and systematically maintained by the manufacturer.

(ii) Process control—

(a) Detailed process specifications shall be laid down by the manufacturer for different stages of manufacture

(b) Equipment and instrumentation facilities shall be adequate to control the processes as laid down in the process specification.

(c) Adequate records shall be maintained by the manufacturer to ensure the possibitity of verifying the controls exercised during the process of manufacture.

(iii) Product Control—

(a) The manufacturer shall have either his own testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to check up whether the product conforms to specifications recognised under section 6 of the Act.

(b) Sampling for test and inspection to be carried out shall be based on the recorded investigation.

(c) Adequate records in respect of sampling and test carried out shall be regularly and systematically maintained.

(d) The minimum levels of control to check the products shall be specified in the shedule.

(iv) Preservation Control—

The product shall be well preserved both during the storage and transit.

(v) Packing Control—

Packing specifications shall be laid down with a view to satisfying the controls as mentioned in the shedule for packing of the products.

SCHEDULE

(1) Levels of Control for Products

[See sub-paragraph(iii) (d) of Annexure—III]

Sl.	Characteristics	Requirements	No. of composite samples to be tested	Frequency	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Total Fatty matter, percent by mass, Min.	As per standard specification	1	Per batch	—
2.	Rosin acids, percent by mass of total fatty matter, Max.	-do-	1	-do-	—
3.	Free Caustic alkali, as sodium hydroxide (NaOH) percent by mass, Max.	-do-	1	-do-	—
4.	Unsaponified fatty matter, percent by mass, Max.	-do-	1	-do-	Whenever applicable
5.	Matter insoluble in alcohol, percent by mass, Max.	-do-	1	-do-	-do-
6.	Moisture and Volatile matter (at 150°C) percent by mass, Max.	-do-	1	-do-	-do-
7.	Matter insoluble in water, percent by mass, Max.	-do-	1	-do-	-do-
8.	Other tests	-do-	1	-do-	-do-

(2) LEVELS OF CONTROL FOR PACKING

[See sub-paragraph (v) of the Annexure-III]

1. The packages containers shall have a good presentability and sufficient strength to stand handing during transit.

2. The following information shall be given on each package/or container namely :—

(a) Name of the material.

(b) Manufacturer's name and trade mark, if any,

(c) Quantity of the material.

(d) Batch number.

ANNEXURE IV

Consignmentwise Inspection

1. The consignment of toilet soaps shall be subjected to inspection and tes'ing to ensure conformity of the same to the standard specifications recognised under section 6 of the Act.

2. In the absence of specific stipulation in the contractual specifications as regards sampling criteria, the same laid down in Table given below shall become applicable.

TABLE

Scale of Sampling

No. of packages in the lot.	No. of packages to be selected at random
(1)	(2)
Upto 3	2
4 to 15	3
16 to 40	4
41 to 65	5
66 to 110	7
111 and above	10

N.B. In a single consignment, all the packages containing toilet soaps of the same type and form, and drawn from the same batch of manufacture, shall constitute a lot.

3. From each one of the package selected as above, draw at random one of more containers for the purpose of sampling.

[No. 6(29)/76-EI&EP]

का० आ० 866.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि संश्लिष्ट अपमार्जक का, निर्यात करने से पूर्व, निरीक्षण किया जाए:

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिये नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव तैयार किया है तथा उसे निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम— 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है:

अतः अब, उक्त उपनियम के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्तावों को उनसे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है।

2. यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे में यदि कोई व्यक्ति आपत्ति या सुझाव भेजना चाहता है तो वह उन्हें इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पंतालीस दिन के भीतर, निर्यात निरीक्षण परिषद् 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर', 14/1-बी०, एजरा स्ट्रीट, (8वीं मंजिल), कलकत्ता को भेज सकता है।

प्रस्ताव

(1) अधिसूचित करना कि संश्लिष्ट अपमार्जक निर्यात करने से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगे :

(2) क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को, इस आदेश के उपाबन्ध-1 में दिए गए संश्लिष्ट अपमार्जक के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1979 के प्रारूप के अनुसार निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना, जो निर्यात से पूर्व ऐसे संश्लिष्ट अपमार्जक को लागू होगा :

(3) (क) संश्लिष्ट अपमार्जक के लिए संश्लिष्ट अपमार्जक के भारतीय मानक विनिर्देशों के नवीनतम विवरण को मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना ।

(ख) उन विनिर्देशों को मान्यता देना जो क्रेता तथा निर्यात-कर्त्ता के बीच हुए करार के अनुसार निर्यात संविदा में संश्लिष्ट अपमार्जक के लिए अनुबद्ध किए जा सकते हैं परन्तु यह तब जब ऐसे विनिर्देश, भारतीय मानक विनिर्देशों के नवीनतम विवरण से निम्न न हों ।

(ग) उन विनिर्देशों को जो उपरोक्त खंड (क) या (ख) के अन्तर्गत नहीं आते हैं, परन्तु निर्यातकर्त्ता द्वारा घोषित ऐसे मानकों के परीक्षण तथा अनुमोदन के प्रयोजन के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल द्वारा अनुमोदित किए गए हैं, संश्लिष्ट अपमार्जक के लिए सांविदिक विनिर्देशों के मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना ।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में ऐसे संश्लिष्ट अपमार्जक के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अभिकरण द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि संश्लिष्ट अपमार्जक उक्त मानक विनिर्देशों के अनुक्रम है या उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिह्न या मोहर उस पर न लगी हो ।

3. इस आदेश की कोई भी बात, भावी क्रेताओं को संश्लिष्ट अपमार्जक (1 कि० ग्रा० से अधिक नहीं) के नमूनों के भू० समुद्र या वायु मार्ग द्वारा निर्यात को लागू नहीं होगी ।

4. इस आदेश में 'संश्लिष्ट अपमार्जक' से घरेलू प्रयोग तथा औद्योगिक कार्यों के लिए प्रयुक्त अल्कली एरिल प्रकार का ऋणायोनिक, असाबुनिक अपमार्जक अभिप्रेत है । कार्यशील अपमार्जक अल्कली एरिल सल्फोनिक अम्ल का सोडियम नमक होगा । उत्पादित वस्तुओं के अन्तिम प्रयोग को ध्यान में रखते हुए उनके स्वरूप में योगशील तैयार करने वाले तत्वों में से एक या अधिक रखे जा सकते हैं सामग्री, मुक्त चूरे, पेस्ट, तरल या गोलियों के रूप में होगी । उसमें कोई अप्रिय गंध नहीं होगी और वह अच्छे झाग देगी ।

उपाबंध-I

[पैरा 2 का उप-पैरा (2) देखिए]

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अधीन बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का प्रारूप ।

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—(i) इन नियमों का नाम, संश्लिष्ट अपमार्जक निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1979 है ।

2. परिभाषा :— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है :

(ख) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन कोचीन, मद्रास, कलकत्ता, मुम्बई, और दिल्ली में स्थापित अभिकरणों में से कोई एक अभिप्रेत है :

(ग) "संश्लिष्ट अपमार्जक" से घरेलू प्रयोग तथा औद्योगिक कार्यों के लिए प्रयुक्त अल्कली एरिल प्रकार का ऋणायोनिक असाबुनीय अपमार्जक अभिप्रेत है । कार्यशील अपमार्जक अल्कली एरिल सल्फोनिक अम्ल का सोडियम नमक होगा । उत्पादित वस्तुओं के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए उनके स्वरूप में योगशील तैयार करने वाले तत्वों में से एक या अधिक रखे जा सकते हैं । सामग्री मुक्त चूरे के, पाउडर, पेस्ट, तरल या गोलियों के रूप में होगी । उसमें कोई अप्रिय गंध नहीं होगी और अच्छे झाग बनाएगी ।

3. निरीक्षण का आधार :— निर्यात के लिए संश्लिष्ट अपमार्जक का निरीक्षण इस दृष्टि से किया जायेगा कि संश्लिष्ट अपमार्जक निर्यात (क्वालिटि नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963(1963 का 22) की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य विनिर्देशों के अनुरूप है या नहीं ।

या

(क) यह सुनिश्चित करते हुए कि वस्तुओं का विनिर्माण उपाबंध II में यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के दौरान आवश्यक क्वालिटी नियंत्रण का योग करते हुए किया गया है ।

या

(ख) उपाबंध III में विनिर्दिष्ट ढंग से किए गए निरीक्षण तथा परिक्षण के आधार पर ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :—(1) संश्लिष्ट अपमार्जक के परेषण का निर्यात कराने का इच्छुक निर्यातकर्ता निर्यात संविदा या आदेश की एक प्रति के साथ संविदागत विनिर्देशों का ब्यौरा देते हुए अभिकरण को लिखित रूप में सूचना देगा जिससे कि अधिनियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर ले ।

(2) निर्यात के लिए संश्लिष्ट अपमार्जक का विनिर्माण, उपाबंध-II में अधिकथित उत्पादन के दौरान पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करते हुए किया गया है तथा यदि परिषद् द्वारा या इस प्रयोजन के लिये परिषद् द्वारा गठित विशेषज्ञों के पैनल द्वारा विनिर्माता यूनिट के संबंध में यह अधिनिर्णय दिया जा चुका है कि उसमें उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण रखने की पर्याप्त व्यवस्था है तो निर्यातकर्ता उपनियम (i) में उल्लिखित सूचना के साथ एक घोषणा भी देगा कि निर्यात के लिए आशयित संश्लिष्ट अपमार्जक के परेषण का विनिर्माण का उपाबंध-II में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करते हुए किया गया है तथा परेषण इस प्रयोजन के लिए मान्य मानक विनिर्देशों के अनुरूप है ।

(3) ऐसी सूचना या घोषणा या दोनों कि एक प्रति एक साथ परिषद के निम्नलिखित कार्यालयों में से एक कार्यालय को जो निरीक्षण के स्थान के निकटतम है, भेजी जाएगी, अर्थात्:—

प्रधान कार्यालय : निर्यात निरीक्षण परिषद,
'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर'
14/1-बी, एज़रा स्ट्रीट,
(8वीं मंजिल),
कलकत्ता-700001.

क्षेत्रीय कार्यालय : निर्यात निरीक्षण परिषद्,
अमन चैम्बर्स,
113, एम कर्वे रोड,
बम्बई-400004.

निर्यात निरीक्षण परिषद,
मनोहर बिल्डिंग,
महात्मा गांधी रोड,
एर्नाकुलम,
कोचीन -6820011.

निर्यात निरीक्षण परिषद,
म्यूनिसिपल मार्केट बिल्डिंग,
3, सरस्वती मार्ग, करौल बाग,
नई दिल्ली-110005

(4) निर्यातकर्ता अधिकरण को परेषण पर लगाए जाने वाला पहचान चिह्न भी देगा।

(5) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा उपनियम (2) के अधीन घोषणा, यदि कोई है, विनिर्माता के परिसर में परेषण के भेजे जाने से कम से कम 7 दिन पहले दी जाएगी।

(6) उप-नियम (1) के अधीन सूचना तथा उपनियम (2) के अधीन घोषणा, यदि कोई है, प्राप्त होने पर अधिकरण :—

(क) अपना यह समाधान कर लेने पर कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान विनिर्माता ने उपाबन्ध II में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग किया है तथा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप उत्पाद के विनिर्माण के संबंध में परिषद् द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का, यदि कोई है, पालन किया गया है, सात दिन के भीतर यह घोषणा करते हुए प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संश्लिष्ट अपमार्जक का परेषण निर्यात-योग्य है। यदि विनिर्माता निर्यात-कर्ता नहीं है तो परेषण का भौतिक रूप से सत्यापन किया जाएगा और ऐसा सत्यापन तथा निरीक्षण आवश्यकतानुसार अधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि उपयुक्त शर्तों का पालन किया गया है। किन्तु अधिकरण निर्यात के लिए आशयित कुछ परेषणों की तत्काल जांच करेगा।

(ख) यदि निर्यातकर्ता ने उपनियम (2) के अधीन यह घोषित नहीं किया है उपाबन्ध II में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग किया गया है तो अपना यह समाधान कर लेने पर कि संश्लिष्ट अपमार्जक का परेषण इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है, उपाबन्ध III में यथा अधिकथित किए गए निरीक्षण परीक्षण के आधार पर या दोनों के आधार पर ऐसा निरीक्षण करने से सात दिन के भीतर यह घोषणा करते हुए प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संश्लिष्ट अपमार्जक का परेषण निर्यात योग्य है।

परन्तु जहां अधिकरण का यह समाधान नहीं हो पाता है, वहां वह उक्त सात दिन की अवधि के भीतर, यह घोषणा करते हुए निर्यात कर्ता को प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार कर देगा कि संश्लिष्ट अपमार्जक का परेषण निर्यात योग्य नहीं है तथा ऐसे इंकार की सूचना उसके कारणों सहित, निर्यातकर्ता को देगा।

(7) जहां विनिर्माता निर्यातकर्ता नहीं है या उपनियम (6) (ख) के अधीन परेषण का निरीक्षण किया गया है या दोनों दशाओं में, अधिकरण निरीक्षण की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् यह सुनिश्चित करने के लिए पैकेजों को परेषण में इस ढंग से सीलबन्द करेगा कि सीलबन्द पैकेजों में हस्तक्षेप न किया जा सके। परेषण की अस्वीकृति की दशा में, यदि निर्यातकर्ता ऐसा चाहे तो, परेषण अधिकरण द्वारा सीलबन्द नहीं किया जाएगा किन्तु ऐसी दशा में निर्यातकर्ता अस्वीकृति के विरुद्ध अपील करने का हकदार नहीं होगा।

5. मान्यताप्राप्त चिह्न चिपकाना तथा उसकी प्रक्रिया :—भारतीय, मानक संस्थान (प्रमाणीकरण चिह्न) अधिनियम, 1952 (1952 का 36) भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणीकरण चिह्न) नियम, 1955 तथा भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणीकरण चिह्न) विनियम, 1955 के उपाबन्ध, निर्यात के लिए आशयित संश्लिष्ट अपमार्जक पर सील या मान्यता प्राप्त चिह्न के चिपकाने की प्रक्रिया के संबंध में यथा संभव लागू होंगे।

6. निरीक्षण स्थान :—इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण या तो, (क) ऐसे उत्पाद के विनिर्माता के परिसर में या (ख) उस परिसर में किया जाएगा जहां निर्यातकर्ता द्वारा माल प्रस्तुत किया गया है परन्तु यह तब जब वहां इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों।

7. निरीक्षण फीस :—प्रत्येक परेषण के लिये न्यूनतम 50 रुपए के अधीन रहते हुए ऐसे प्रत्येक परेषण के लिये पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रति सौ रुपये के लिये पचास पैसे की दर से फीस, निरीक्षण फीस के रूप में दी जायगी।

8. अपील :—(1) नियम 4 के उपनियम (4) के अधीन प्रमाणपत्र देने से इंकार किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने से दस दिन के भीतर, इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात व्यक्तियों के ऐसे विशेषज्ञों के पैनल को कर सकता है।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता में कम से कम दो-तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन से होगी।

(4) विशेषज्ञों का पैनल अपील प्राप्त होने से पन्द्रह दिन के भीतर उसे निपटा देगा।

उपाबन्ध II

[नियम 3(क) के अन्तर्गत देखिए]

(i) क्वालिटी नियंत्रण

विनिर्माता, संश्लिष्ट उपमार्जक पर क्वालिटी नियंत्रण, नीचे अधिकथित उत्पादों के विनिर्माण, अनुरक्षण और पैक करने के विभिन्न प्रक्रमों पर निम्नलिखित नियंत्रण रख कर तथा इसे संलग्न अनुसूची में वर्णित नियंत्रण स्तरों के अनुसार, सुनिश्चित करेगा, अर्थात् :—

(1) क्रय तथा कच्ची सामग्री नियंत्रण—

(क) प्रयुक्त की जाने वाली कच्ची सामग्री की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए विनिर्माता क्रय विनिर्देश अधिकथित करेगा।

(ख) स्वीकृत परेषणों के साथ या तो क्रय विनिर्देशों की अपेक्षाओं की पुष्टि करते हुए प्रदायकर्ता का परख या निरीक्षण प्रमाणपत्र होगा, जिस दशा में क्रेता द्वारा विशिष्ट प्रदायकर्ता के लिये उक्त परख या निरीक्षण प्रमाणपत्र की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए 10 परेषणों में से कम से कम एक की यदा कदा जांच की जायगी या क्रय की गई सामग्री का या तो कारखाने के भीतर प्रयोगशाला में या बाहरी प्रयोगशाला में परख गृह में नियमित रूप से परीक्षण और निरीक्षण किया जायगा।

(ग) निरीक्षण या परख के लिये नमूने का लिया जाना, अभिलिखित अन्वेषण पर आधारित होगा।

(घ) निरीक्षण या परीक्षण किए जाने के बाद, स्वीकृत और अस्वीकृत माल को पृथक करने तथा अस्वीकृत माल के निपटारे के लिये व्यवस्थित पद्धतियां अपनाई जाएंगी।

(ङ) विनिर्माता द्वारा उक्त नियंत्रण के बारे में पर्याप्त अभिलेख नियमित रूप से तथा व्यवस्थित रूप से रखा जायगा।

(ii) प्रक्रिया नियंत्रण

(क) विनिर्माण के विभिन्न प्रक्रमों के लिये विनिर्माता, विस्तृत प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित करेगा।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देश में अधिकथित प्रक्रियाओं के नियंत्रण के लिये उपस्कर तथा यंत्रसमुच्चय की पर्याप्त सुविधाएं होंगी।

(ग) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रयोग किए गए नियंत्रणों के सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिये विनिर्माता पर्याप्त अभिलेख रखेगा।

(iii) उत्पाद नियंत्रण

(क) यह जांच करने के लिये कि उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्य विनिर्देशों के अनुरूप है, या तो परीक्षण करने के लिये विनिर्माता के पास ही परख सुविधाएं होंगी या उसकी पहुंच वहां तक होगी जहां ऐसी सुविधाएं विद्यमान हैं।

(ख) परख या निरीक्षण के लिये नमूने का लिया जाना अभिलिखित अन्वेषण पर आधारित होगा

(ग) नमूने लेने तथा किए गए परीक्षणों के संबंध में पर्याप्त अभिलेख नियमित तथा व्यवस्थित रूप में रखा जायगा।

(घ) उत्पाद की जांच करने के लिये न्यूनतम नियंत्रण स्तर अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

(iv) परिरक्षण नियंत्रण

भंडारकरण तथा अभिवहन, दोनों के दौरान, उत्पाद को भली-भांति परिरक्षित किया जायगा।

(v) पैकिंग नियंत्रण

उत्पाद की पैकिंग के लिए, पैकिंग विनिर्देश, अनुसूचि में वर्णित नियंत्रणों को पूरा करते हुए अधिकथित किए जाएंगे।

अनुसूची

उत्पादकों के लिए नियंत्रण के स्तर

उपाबंध II का उप पैरा (iii)(घ) देखिए।

क्रम सं०	विशेषताएं	अपेक्षाएं	परख किए जाने वाले नमूनों की संख्या	आवृत्ति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	सक्रिय संघटक	मानक विनिर्देशों के अनुसार	1	प्रति बैच	—
2.	सोडियम ट्राइफोली फासफेट	—यथोक्त—	1	—यथोक्त—	—
3.	1 प्रतिशत घोल का पी०एच० 27/° से० पर	—यथोक्त—	1	—यथोक्त—	—
4.	आर्द्रता तथा वाष्पशील पदार्थ 105/° से० पर	—यथोक्त—	1	—यथोक्त—	जब कभी लागू हो
5	पानी में अविलेप पदार्थ	—यथोक्त—	1	—यथोक्त—	—यथोक्त—
6.	अल्कोहल में अविलेप पदार्थ	—यथोक्त—	1	—यथोक्त—	—यथोक्त—
7.	स्पष्ट बिन्दु	—यथोक्त—	1	—यथोक्त—	—यथोक्त—
8.	अप्रक्षालक कार्बनिक पदार्थ	—यथोक्त—	1	—यथोक्त—	—यथोक्त—
9.	अन्य परख	—यथोक्त—	1	—यथोक्त—	—यथोक्त—

(2) पैकिंग के लिये नियंत्रण के स्तर

(उपाबंध–II का उपपैरा (v) देखिए)

1. पैकेज 1 डिब्बे मुडौल और अभिवहन के दौरान उठाई-धराई की दृष्टि से पर्याप्त क्षमता वाले होंगे।

2. प्रत्येक पैकेज 1 डिब्बे पर निम्नलिखित का उल्लेख होगा, अर्थात :—

(क) माल का नाम।

(ख) विनिर्माता का नाम तथा 'व्यापार चिह्न' यदि कोई हो।

(ग) माल की मात्रा।

(घ) बैच संख्या।

उपाबंध III

परेक्षणानुसार निरीक्षण

1. संश्लिष्ट अपमार्जक के परेषण का निरीक्षण तथा परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिये किया जायगा कि वह अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

2. नमूने मानदण्ड के लिये संविदागत विनिर्देशों में विनिर्दिष्ट अनुबंध के न होने पर, निम्नलिखित सारणी में दिए गए मानदण्ड लागू होंगे।

सारणी

नमूने लेने के लिए मान मान

सं०	लाट में पैकेजों की सं०	यादृच्छिक चुने जाने वाले पैकेजों की सं०
1	2	3
	3 तक . .	2
	6 से 15 तक . .	3
	16 से 40 तक . .	4
	41 से 65 तक . .	5
	66 से 110 तक . .	7
	111 से अधिक . .	10

टिप्पणी : एक परेषण में, विनिर्माण के उसी बैच से लिये गए तथा एक ही आकार प्रकार वाले संश्लिष्ट अपमार्जक के सभी पैकेज एक लाट का गठन करेंगे।

उपरोक्त रूप में लिये गये पैकेजों में से, नमूना लेने के प्रयोजनार्थ, यादृच्छिक एक या अधिक डिब्बे लिये जायेंगे।

[सं० 6(28)/78-नि०नि० तथा नि०उ०]

S.O. 866.—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India that synthetic detergents should be subject to inspection prior to export ;

And whereas the Central Government has formulated the proposal specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council, as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 ;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within fortyfive days of the date of publication of this order in the Official Gazette to the Export Inspection Council "World Trade Centre", 14/1B Ezra Street (7th floor), Calcutta-1.

PROPOSALS

(1) To notify that synthetic detergents shall be subject to quality control and inspection prior to export ;

(2) To specify the type of quality control and inspection in accordance with the draft Export of Synthetic Detergents (Quality control and Inspection) Rules, 1979 set out in Annexure I to this order as the type of quality control and inspection which would be applied to such synthetic detergents prior to export ;

(3) To recognise.—

(a) the latest version of Indian Standard specification of synthetic detergents as the standard specifications for synthetic detergents.

(b) the specifications which may be stipulated for synthetic detergentns in the export contract as agreed between the buyer and the exporter provided that such specifications do not fall below the latest version of the Indian Standard specifications,

(c) the specifications which do not fall under clause (a) or (b) above, but are approved by the panel of Expert, appointed by the Export Inspection Council for the purpose of examining and approving such standards declared by the exporter as contractual specifications as the standard specifications for synthetic detergents.

(4) To prohibit the export, in the course of International trade of such synthetic detergents unless the same is accompanied by a certificate issued by an agency established by the Central Government under section 7 of the Export (Quality control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963 to the effect that the synthetic detergents conform to the aforesaid standard specifications or affixed with a seal or mark recognised by the Central Government under section 8 of the said Act.

3. Nothing in this order shall apply to the export by land, sea or air of samples of synthetic detergents (Not exceeding 1 kg.) to the prospective buyers.

4. In this order "synthetic detergents" shall mean 'anionic nonsoapy detergents of the alkyl aryl type' used for household use and industrial purposes. The active ingredient shall be the sodium Salt of alkyl aryl sulphonic acid. The formulation may contain one or more of the builders of additives keeping in view of the end use of the product. The material shall be in the form of a free flowing powder, paste, liquid or tablets, shall not give any unpleasant odour and shall give good lather.

ANNEXURE I

[See sub-paragraph (2) of paragraph 2]

Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963)

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Synthetic Detergent (Quality Control and Inspection) Rules, 1979.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963)

(b) "agency" means any one of the agencies established under section 7 of the act at Cochin, Madras, Calcutta, Bombay and Delhi :

(c) "synthetic detergent" means anionic non-soapy detergents of the alkyl aryl type, used for household use and industrial purposes. The active ingredient shall be the sodium salt of alkyl aryl sulphonic acid. The formulation may contain one or more of the builders of additives keeping in view of the end use of the product. The material shall be in the form of a free flowing powder, paste, liquid or tablets, shall not give any unpleasant odour and shall give good lather.

3. Basis of Inspection.— Inspection of synthetic detergents for export shall be carried out with a view to seeing that the synthetic detergents conform to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963),

either,

(a) by ensuring that the products have been manufactured by exercising necessary in-process quality control as specified in Annexure-II

or,

(b) on the basis of inspection and testing carried out in the manner specified in Annexure-III.

4. Procedure of Inspection.—(1) An exporter intending to export a consignment of synthetic detergents shall give an intimation in writing to the agency furnishing therein details of the contractual specifications along with a copy of the export contract or order to enable the agency to carry out inspection in accordance with rule 3.

(2) For export of synthetic detergents manufactured by exercising adequate in-process quality control as laid down in Annexure-II and in case the manufacturing unit has been adjudged as having adequate in-process quality control drills by the Council or panel of Experts constituted by the Council for this purpose, the exporter shall also submit along with the intimation mentioned in sub-rule (1) a declaration that the consignment of synthetic detergents intended for export has been manufactured by exercising adequate quality control as laid down in Annexure-II and that the consignment conforms to the standard specifications recognized for the purpose.

3. A copy of each such intimation or declaration or both shall also be simultaneously endorsed to any of the following offices of the Council, which is nearest to the place of inspection, namely :

Head Office :	Export Inspection Council, 'World Trade Centre' 14/1B, Ezra Street (7th floor) Calcutta-7000001.
Regional Offices :	Export Inspection Council, Aman Chambers, 113, M. Karve Road, Bombay-400004.
	Export Inspection Council, Manohar Buildings, Mahatma Gandhi Road, Ernakulam, Cochin-682001.
	Export Inspection Council, Municipal Market Building 3, Saraswati Marg, Karol Bagh, New Delhi-110005.

(4) The exporter shall also furnish to the agency the identification marks applied on the consignment.

(5) Every intimation under sub-rule (1) and declaration, if any, under sub-rule (2) above shall be given not less than seven days perior to the despatch of the consignment from the manufacturers premises.

(6) on receipt of the intimation under sub-rule (1) and the declaration, if any, under sub-rule (2), the agency —

(a) on satisfying itself that during the process of manufacture, the manufacturer had exercised adequate quality control as alid down in Annexure-II and followed the instructions, if any, issued by the Council in this regard to manufacture the product to conform to the standard specifications recognised for the purpose, shall within seven days issue a certificate declaring the consignment of synthetic detergents as exportworthy. In cases where the manufacturer is not the exporter, however, the consignment shall be physically verified and such verification and inspection as necessary shall be carried out by the agency to ensure that the above conditions are complied with The agency shall, however, conduct spot checks of some of the consignments meant for export ;

(b) in cases where the exporter has not declared under sub-rule (2) that adequate quality control as laid down in Annexure-II had been exercised, on satisfying itself that the consignment of synthetic detergents conforms to the standard specifications recognized for the purpose, on the basis of inspection or testing carried out as laid down in Annexure-III, or on the basis of both, shall, within seven days of carrying out such inspection issue a certificate declaring the consignment of synthetic detergents as exportworthy ;

Provided that where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of seven days refuse to issue a certificate to the exporter declaring the consignment of synthetic detergents as exportworthy and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.

(7) In cases where the manufacturer is not the exporter or the consignment is inspected under sub-rule (6) (b), or in both the cases the agency shall, immediately after completion of the inspection, seal the packages in the consignment in a manner as to ensure that the sealed packages cannot be tampered with. In case of rejection of the consignment, if the exporter so desires, the consignment may not be sealed by the agency, but in such cases however, the exporter shall not be entitled to prefer any appeal against the rejection.

5. Affixation of recognised mark and procedure thereof.— The provisions of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 (36 of 1952), the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 and the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulation, 1955 shall, so far as may apply in relation to the procedure of affixation of the recognised mark or seal on synthetic detergents meant for export.

6. Place of Inspection.—Every inspection under these rules shall be carried out either (a) at the premises of the manufacturer of such product ; or (b) at the premises at which the goods are offered by the exporter provided adequate facilities for the purpose exist therein.

7. Inspection Fee.— Subject to a minimum of Rs. 50/- for each consignment, a fee at the rate of fifty paise for every one hundred rupees of the f.o.b. value for each such consignment shall be paid as inspection fee.

8. Appeal.— (1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a Certificate under sub-rule (4) of rule 4, may, within ten days of the receipt of communication of such refusal by him, prefer an appeal to such panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons as may be constituted by the Central Government for the purpose.

(2) The panel of experts shall consist of at least two-thirds of non-officials of the total memberships of the panel of experts.

(3) The quorum for the panel of experts shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of by the panel of experts within fifteen days of its receipt.

ANNEXURE II

[SEE UNDER RULE 3 (a)]

Quality Control—

The quality control of synthetic detergents shall be ensured by the manufacturer by effecting the following controls at different stages of manufacture preservation and packing of the products as laid down below, together with the levels of control as set out in the schedule appended hereto.

(1) Purchase and raw material control—

(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of raw materials to be used.

(b) Either the accepted consignments shall be accompanied by a supplier's test and inspection certificate corroborating the requirements of the purchase specifications, in which case occasional checks shall be conducted at least once in 10 consignments by the purchaser for a particular supplier to verify the correctness of the aforesaid test or inspection certificate or the purchased material shall be regularly tested and inspected either in the laboratory within the factory or in an out side laboratory or test house

(c) The sampling for inspection or test to be carried out shall be based on the recorded investigations.

(d) After the inspection or test is carried out systematic methods shall be adopted in segregating the accepted and relected materials and for disposal of the relected materials.

(e) Adequate records in respect of the aforesaid controls shall be regularly and systematically maintained by the manufacturer.

(ii) Process Control—

(a) Detailed process specifications shall be laid down by the manufacturer for different stages of manufacture.

(b) Equipment and instrumentation facilities shall be adequate to control the processes as laid down in the process specifications.

(c) Adequate records shall be maintained by the manufacturer to ensure the possibility of verifying the controls exercised during the process of manufacture.

(iii) Product Control—

(a) The manufacturer shall have either his own testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to check up whether the product conforms to specifications recognised under section 6 of the Act.

(b) Sampling for test and inspection to be carried our shall be based on the recorded investigation.

(c) Adequate records in respect of sampling and test carried out shall be regularly and systematically maintained.

(d) The minimum levels of control to check the products shall be as specified in the schedule.

(iv) Preservation Control—

The product shall be well preserved both during the storage and transit.

(v) Packing Control—

Packing specifications shall be laid down with a view to satisfying the controls as mentioned in the schedule for packing of the products.

SCHEDULE

1. Levels of Control for Products

[See sub-paragraph (iii) (d) of Annexure-II]

Sl. No.	Characteristics	Requirements	No. of samples to be tested	Frequency	Remarks
1.	Active ingredient	As per standard specifications	1	Per batch	—
2.	Sodium tripoly-phosphate (STPP).	-do-	1	-do-	—
3.	PH of 1% solution at 27°C.	-do-	1	-do-	—
4.	Moisture and volatile matter content at 105°C.	-do-	1	-do-	Whenever applicable
5.	Matter in soluble in water.	-do-	1	-do-	-do-
6.	Matter in soluble in Alcohol.	-do-	1	-do-	-do-
7.	Clear Point.	-do-	1	-do-	-do-
8.	Non-detergent organic matter	-do-	1	-do-	-do-
9.	Other tests.	-do-	1	-do-	-do-

1240 GI/78—4

2. Levels of Control for Packing

[See sub-paragraph (v) of Annexure-II]

1. The packages/containers shall have a good presentability and sufficient strength to stand handling during transit.

2. The following information shall be given on each package container, namely :—

(a) Name of the material

(b) Manufacturer's name and trade mark, if any.

(c) Quantity of the material.

(d) Batch number.

ANNEXURE III

Consignmentwise Inspection—

1. The consignment of synthetic detergents shall be subjected to inspection and testing to ensure conformity of the same to the standard specifications recognised under section 6 of the Act.

2. In the absence of specific stipulation in the contractual specifications as regards sampling criteria, the same laid down in Table given below shall become applicable.

[No. 6(28)/76-EI&EP]

TABLE

Scale Of Sampling

No. of packages in the lot.	No. of packages to be selected at random
Up to 3	2
4 to 15	3
16 to 40	4
41 to 65	5
66 to 110	7
111 and above	10

N.B.—In a single consignment of the package containing synthetic detergent of the same type and form, and drawn from the same batch of manufacture, shall constitute a lot.

From each one of the packages selected as above, draw at random one or more contents for the purpose of sampling.

[No. 6(28)/76-EI&EP]

का० आ० 867.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह उपवर्णित करने के प्रयोजन के लिए संश्लिष्ट अपमार्जक के लिए संबंध में भारतीय मानक संस्थान प्रमाणीकरण चिन्ह को मान्यता देने का प्रस्ताव करती है कि जहां संश्लिष्ट अपमार्जक के डिब्बों या पैकेजों पर ऐसे चिन्ह चिपकाए या लगाए जाएं तो वे उक्त अधिनियम के अधीन उसे लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप समझे जाएंगे ।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्ताव को निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है :

अतः अब, उक्त उप-नियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्ताव को उन सभी लोगों की जानकारी के लिए, प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ।

2. सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्ताव के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता है तो वह उसे इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद् "वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर" 14/1-बी० एजरा स्ट्रीट (8वीं मंजिल) कलकत्ता-700001 को भेज सकता है ।

3. इस आदेश के प्रयोजन के लिए 'संश्लिष्ट अपमार्जक' से, बरेलू प्रयोग तथा औद्योगिक प्रक्षालक अभिप्रेत है । सक्रिय प्रक्षालक अकली एरिल सल्फोनिक अम्ल का सोडियम नमक होगा । उत्पादित वस्तुओं के

अन्तिम प्रयोग को ध्यान में रखते हुए, उसके स्वरूप में योगशील तैयार करने वाले तत्वों में से एक या अधिक रखे जा सकते हैं । सामग्री, मुक्त प्रवाही चूरे, पेस्ट, तरल या गोलियों के रूप में होंगी । उसमें कोई अप्रिय गंध नहीं होगी और वह अच्छे झाग देगी ।

[सं० 6(28)/76-नि०नि० तथा नि० उ०]

S.O. 867.—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 8 of the Export Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), proposes to recognise the Indian Standards Institution certification mark in relation to synthetic detergents for the purpose of denoting that where the cartons or packages of synthetic detergents are affixed or applied with such mark. They shall be deemed to be in conformity with the standard specifications applicable thereto under the said Act.

And, whereas the Central Government has forwarded the aforesaid proposal to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule (ii) of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 ;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule the Central Government hereby publishes the said proposal for the information of public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposal may forward the same within forty-five days of the publication of this notification in the Official Gazette to Export Inspection Council, 'World Trade Centre' 14/1B Ezra Street (7th floor), Calcutta-700001.

3. For the purpose of this notification 'synthetic detergents' means a anionic nonsoapy detergents of the alkyl aryl type' used for household use and industrial purposes. The active ingredient shall be the sodium salt of alkyl sulphonic acid. The formulation may contain one or more of the builders of additives keeping in view of the end use of the product. The material shall be in the form of a free flowing powder, paste, liquid or tablets shall not give any unpleasant odour and shall give good lather.

[No. 6(28)/76/EI&EP]

का० आ० 868.—केन्द्रीय सरकार (निर्यात क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए कि प्रसाधन के लिए साबुन के संबंध में भारतीय मानक संस्थान प्रमाणीकरण चिन्ह को मान्यता देने का प्रस्ताव करती है कि जहां प्रसाधन के लिए साबुन के डिब्बों या पैकेजों पर ऐसे चिन्ह लगाए या चिपकाए या लगाए जाए तो वे उक्त अधिनियम के अधीन उसे ला मानक विनिर्देशों के अनुरूप समझे जाएंगे ।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों को निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है ।

अतः, अब, उक्त उप-नियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्तावों को उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ।

2. सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्ताव के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता है तो वह उन्हें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद् 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर' 14/1-बी०, एजरा स्ट्रीट (7वीं मंजिल) कलकत्ता-1 को भेज सकता है ।

3. इसमें 'प्रसाधन के लिए साबुन' से प्रसाधन का अपारदर्शी या पारदर्शी साबुन, पूरी तरह साबुनीकृत मशीन से तैयार किया गया, उसके बिना तैयार किया गया या समाप्तीकृत सफेद या रंगीन या पारदर्शी साबुन जो सुगन्धित तथा पक्की चिकनी टिक्की के रूप में तैयार किया गया है अभिप्रेत है, जिसमें अच्छी सफाई करने तथा झाग देने की विशेषताएं हों । सुगन्ध तथा आर्द्रता तथा वाष्पशील पदार्थ के अतिरिक्त प्रसाधन के लिए साबुन में रंजक पदार्थ, परिरक्षक, औषधि, अतिवसायम पदार्थ तथा ऐसे अतिरिक्त पदार्थ हो सकते हैं, जो कि लेबल पर घोषित किए गए हैं तथापि सभी पूर्वोक्त पदार्थ जब साबुन में मिले हों, प्रयोग में हानि रहित होंगे ।

[सं० 6(29)/76-नि० नि० तथा नि० उ०]

सी० बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

S.O. 868.—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 8 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), proposes to recognise the Indian Standards Institution Certification mark in relation to toilet soaps for the purpose of denoting that where the cartons or packages relating to toilet soaps are affixed or applied with such mark, they shall be deemed to be in conformity with the standard specifications applicable thereto under the said Act ;

And, whereas the Central Government has forwarded the aforesaid proposal to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 ;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule the Central Government hereby publishes the said proposal for the information of public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposal may forward the same within forty-five days of the publication of this notification in the official Gazette to Export Inspection Council, 'World Trade Centre' 14/1B Ezra Street (7th floor), Calcutta-700 001.

3. In this order "toilet soaps" shall mean opaque or transparent toilet soaps, thoroughly saponified, mild or unmiled soap or homo-ganized soap, white or coloured or transparent perfumed, and compressed in the form of firm smooth cakes, and shall possess good cleaning and lathering properties. In addition to perfume and moisture, and volatile matter, toilet soaps may contain only colouring matter, preservatives, medicaments, superfatting agents and such additional substances as are declared on the level. The transparent toilet soap may contain sugar and glycerol. However all the foregoing materials shall be non-injurious in use with soap.

[No. 6(29)/76-EI&EP]

C. B. KUKRETI, Jt. Director.

(मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1979

का० आ० 869.—सर्वश्री डब्ल्यू० एच० ब्रेडी एंड कं० लि०, 12-14, वीर नेरियन रोड, बंबई को अप्रैल, 77-मार्च 78 की लाइसेंस अवधि के लिए यू० के० भारत अनुरक्षण अनुबन्ध-77 के अंतर्गत अप्रैल-मार्च 77-78 अवधि की नीति के अनुसार यू० के० मूल की मशीनरी और उपकरणों के लिए अपेक्षित अनुमेय किस्म के फालतू पुर्जों और लाइसेंस के लिए संलग्न सूची के अनुसार 10,00,000/—रु० मात्र (दस लाख रुपये मात्र) मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं० पी/ई/2811072/आर/एमजी/65/एच/77, दिनांक 8-12-77 प्रदान किया गया था । जो कि 8-12-78 तक वैध था । अब लाइसेंसधारी ने इस कार्यालय से उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि सर्वश्री ट्रैक्टर स्पेयर्स कार्यों, बंबई के लिए जारी किए गए 9,00,000 रुपये के प्राधिकरण पत्र और उक्त लाइसेंस के लिए संलग्न सूची के साथ मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति बंबई के सीमा-शुल्क कार्यालय द्वारा, जो

गई/अस्थानस्त हो गई है । उन्होंने आगे बताया है कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति अम्बई के सीमा-शुल्क समाहर्ता के पास पंजीकृत कराई गई है और उसका आंशिक रूप से उपयोग कर लिया गया है ।

2. अपने तर्क के समर्थन में, आवेदक ने स्टैम्प कागज पर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस सं० पी/ई/2811072/आर/एमजी/65/एच/77 दिनांक 8-12-77 की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति आवेदक द्वारा खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता है कि उन्हें शेष 8,49,131 रुपये मात्र के उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति जारी की जानी चाहिए । आयात लाइसेंस संख्या पी/ई/2811072/आर/एमजी/65/एच/77, दिनांक 8-12-77 की मूल सीमा-शुल्क प्रति प्रयोजन एतद् द्वारा रद्द की जाती है ।

[सं० 49/यूकेआईएमजी/77-78/जीएलएस/681]

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 18th February, 1979

S.O. 869.—M/s. W. H. Brady & Co. Ltd., 12—14 Veer Narain Road, Bombay were granted an import licence No. P/E/2811072|R|MG|65|H|77, dated 8th December, 1977 valid upto 8th December, 1978 for import of Permissible types of spares required for Machinery and Equipments of U.K. origin as per policy for the Period AM 77-78 and also as per list attached for the value of Rs. 10,00,000 only (Rupees ten lakhs only) under U.K.-India Maintenance Grant 77 for the licensing period April, 1977—March, 1978. Now the licensee has requested this office for the issue of duplicate Customs Purpose Copy of the said licence on the ground that the original Cutoms Purpose Copy of the said licence alongwith the list of goods attached thereto and Letter of authority for Rs. 9,00,000 only in favour of M/s. Tractor Spares Corpn. Bombay have been lost/misplaced by the Customs House Bombay. They have further stated that the original Customs Purpose Copy of the said licence had been registered with the Collector of Customs, Bombay and utilised partly.

2. In support of their contention, the applicant has filed an affidavit on Stamped paper. The undersigned is satisfied that the original Customs Purposes Copy of licence No. P/E/2811072/R/MG/65/R/77, dated 8th December, 1977 has been lost/misplaced by the applicant and directs that duplicate Customs Purposes Copy of the said licence for balance of Rs. 8,49,181 only should be issued to them. The original Customs Purpose Copy of the import licence No. P/E/2811072/R/MG/65/H/77, dated 8th December 1977 is hereby cancelled.

[No. 49/UKIMG/77-78/GLS/681]

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1979

का० आ० 870—सर्वश्री (एम एण्ड टी), रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली को लाइसेंस अवधि अप्रेल-75—मार्च-76 के लिए सर्वश्री मित्सुई एण्ड कं० लि०, जापान से लाइसेंस की संलग्न सूची के अनुसार माइक्रोवेव संघटकों के पुर्नस्थापन के आयात के लिए रेलवे संविदा के मुद्दे 11,354 रुपए मात्र मूल्य का एक आयात लाइसेंस (सीमा शुल्क निकासी परमिट) संख्या जी/जे/3042586/क्यू०/डब्ल्यू डब्ल्यू//56/एच, दिनांक 11-9-75 प्रदान किया गया था, जो 31-3-76 तक वैध था ।

2. अब लाइसेंसधारी ने इस कार्यालय से सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट खो गया/अस्थानास्थ हो गया है । उसने आगे यह भी बताया कि सीमा शुल्क किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कराया गया है । उसका बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया है ।

3. अपने तर्क के समर्थन में, आवेदक ने स्टैम्प पेपर पर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि आवेदक द्वारा मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट संख्या जी/जे/3042586/क्यू/डब्ल्यू डब्ल्यू/56/एच, दिनांक 11-9-75 खो गया/अस्थानस्थ हो गया है और निदेश देता है कि उसे पूरे मूल्य की सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी की जानी चाहिए । मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट संख्या जी/जे/3042586/क्यू/डब्ल्यू० डब्ल्यू/56/एच, दिनांक 11-9-75 एतद्-द्वारा रद्द किया जाता है ।

[संख्या 19-एस/रेलवे/75-76/जीएलएस/714]

चन्द्र सैन आर्य, उप-मुख्य नियंत्रक

New Delhi, the 22nd February, 1979

S.O. 870.—The Secretary (S&T), Ministry of Railway, Railway Board, Rail Bhavan, New Delhi was granted an import licence (CCP) No. G/J/3042586/C/WW/56/H, dated 11th September, 1975 valid upto 31st March, 1976 for the import of replacement of Microwave Components as per list attached from M/s. Mitsui & Co. Ltd., Japan for the value of Rs. 11,354 only against Railway Contract for the licensing period April, 1975—March, 1976.

2. Now the licensee has requested the office for the issue of Duplicate copy of CCP on the ground that the original CCP has been lost/misplaced. He has further stated that the original CCP has not been registered with any Customs authority/utilised at all.

3. In support of his contention, the applicant has filed an affidavit on Stamped paper. The undersigned is satisfied that the original CCP No. G/J|3042586|C|WW|56|H, dated 11th September, 1975 has been lost/misplaced by the applicant and directs that the duplicate copy of CCP for full value should be issued to him. The original CCP No. G/J/3042586|Q|WW|56|H, dated 11th September, 1975 is hereby cancelled.

[No. 19-S/Rly./75-76/GLS/714]

C. S. ARYA, Dy. Chief Controller

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1979

का० आ० 871.—डा० डी० के० टंडन, 22/128 जी एस वी रोड, कानपुर, यूपी, जिन्हें एस ए ए बी—99, 1971 मॉडल कार, चेसिस सं० 99060099 के आयात के लिए 20,000 रुपये मात्र का एक सीमा-शुल्क निकासी परमिट सं० पी/जे/3057508/एन/एम पी/69/एच/78, दिनांक 2-12-78 प्रदान किया गया था। उन्होंने सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट खो गया है। आगे यह बताया गया है कि मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट किसी भी सीमाशुल्क कार्यालय के पास पंजीकृत नहीं कराया गया था और उसका उपयोग नहीं किया गया था।

इस तर्क के समर्थन में डा० डी० के० टंडन ने एक शपथपत्र दाखिल किया है। उन्होंने वचन दिया है कि यदि सीमा-शुल्क निकासी परमिट बाद में मिल गया तो वह उसे इस कार्यालय को रिकार्ड के लिए लौटा देंगे। मैं संतुष्ट हूं कि मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट सं० पी/जे/3057508/एन/एम पी/69/एच/78, दिनांक 2-12-78 खो गया है और निदेश देता हूं कि उन्हें अनुलिपि सीमा-शुल्क निकासी परमिट जारी किया जाए। मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट रद्द किया गया समझा जाए।

[मिसिल सं० 2 (बी-80) /78-79/बीएलएस/2780]

ए० एन, चेटर्जी, उप-मुख्य नियंत्रक,

New Delhi, the 24th February, 1979

S.O. 871.—Dr. D. K. Tandon, 22/128, G. S. V. Road Kanpur, U. P. who was granted Custom Clearance Permit No. P/J/3057508/N/MP. 69/H/78 dated 2-12-1978 has been lost and direct that a duplicate for import of a SAAB-99, 1971 Model car, Chassis No. 99060099, has applied for a duplicate copy of the Custom Clearance Permit as the original C. C. P. has been lost. It is further stated that the original CCP was not registered with any Custom House and not utilised.

In supoort of this contention Dr. D. K. Tandon has filed an affidavit. He has undertaken to return the C. C. P. if traced later to this office for record. I am satisfied that the original C. C. P. No. P/J/3057508/N/MP/69/H/78, dt : 2-12-78. has been lost and direct that a duplicate C. C. P. should be issued to him. The original Custom Clearance Permit may be treated as cancelled.

[F. No. 2 (B-80)/78-79/BLS/2780]

A. N. CHATTERJEE, Dy. Chief Controller

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1979

का० आ० 872/आव० वस्तु नमक (3):—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नमक (आरक्षित भण्डार) आदेश, 1955 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का नाम नमक (आरक्षित भण्डार) संशोधन आदेश, 1979 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. नमक (आरक्षित भण्डार) आदेश, 1955 में,—

(क) पैरा 3 में, "नमक का प्रत्येक आयातकर्त्ता" से आरम्भ होकर "गोला में भण्डार के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा" पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1) "नमक का प्रत्येक आयातकर्त्ता, अपने द्वारा आयातित कलकत्ता या बढ़िया नमक में से प्रत्येक का कम से कम 5 प्रतिशत भाग सरकारी, गोला, कलकत्ता में भण्डार करेगा, परन्तु नमक आयुक्त समय समय पर, इस प्रकार भण्डार किए जाने वाले नमक की प्रतिशतता में इतना परिवर्तन कर सकता है कि वह पन्द्रह प्रतिशत से अधिक न हो जाए, और ऐसा करने में, वह ऐसी अवधि विनिर्दिष्ट करेगा जिसमें यह अपेक्षित होगा कि आयातकर्त्ता, नमक की और अधिक मात्रा गोला में आरक्षित भण्डार के रूप में रखे जाने के लिए प्रस्तुत नहीं करेगा।

(2) नमक आयुक्त, उपपैरा (1) के अधीन भण्डार किए जाने वाले नमक की प्रतिशतता में परिवर्तन करते समय, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:—

(क) आयातकर्त्ताओं द्वारा, समय समय पर आयातित नमक की मात्रा;

(ख) सरकारी गोलाओं में उपलब्ध नमक का आरक्षित भण्डार,

(ग) कोई अन्य विषय, जो नमक आयुक्त की राय में इस प्रयोजन के लिए सुसंगत है।"

(ii) खण्ड (ग) में, "आयातकर्त्ता" से आरम्भ होकर "किराए का संदाय करेगा" पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"आयातकर्त्ता, आरक्षित भण्डार में नमक के भण्डारकरण और हटाए जाने के संबंध में साल्ट कमिश्नर गोला के प्रशासन के बारे में नियमों के उपबंधों का पालन करेंगे।"

(ख) पैरा 4 में, "पैरा 3 के अधीन भण्डारित नमक की मात्राएं" से आरम्भ होकर "न तो बेचेगा और न व्ययन करेगा"। पर समाप्त होने वाले भाग के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"आरक्षित भण्डार सामान्यतः एक वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा, परन्तु नमक आयुक्त द्वारा समय-समय पर विहित आरक्षित भण्डार जैसे ही अधिकतम सीमा पार करेगा, वैसे ही 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर भण्डार से निकासी की जा सकेगी। फिर भी नमक आयुक्त, यदि परिस्थिति से अपेक्षित है तो, इस अवधि को बढ़ा सकता है।"

[फा० सं० 05018/3/71-नमक]

के० के० जसवाल, उप सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 6th February, 1979

S.O. 872./Ess. Comm. Salt (3).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend Salt (Reserve Stock) Order, 1955, namely :—

1. (1) This Order may be called "The Salt (Reserve Stock) Amendment Order, 1979.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Salt (Reserve Stock) Order, 1955

(a) In paragraph 3, for the portion beginning with the words "Every importer of salt shall store" and ending with the words "for storage in the Golahs" the following shall be substituted, namely :—

(1) "Every importer of salt shall store not less than five per cent of the quantity of each of the different varieties of salt (that is Kurkutch or Fine) imported by him, in the Government Golah at Calcutta, but the Salt Commissioner may vary, from time to time, the percentage of salt to be stored so, however, as not to increase it above fifteen per cent, and in doing so may also, for such period as he may specify require that no further quantity of salt shall be offered by any importer for storage of salt as reserve stock in the Golahs.

(2) While varying the percentage of salt to be stored under sub-paragraph (1), the Salt Commissioner shall have regard to the following matters namely :—

(a) the quantity of salt imported by the importers, from time to time;

(b) the reserve stock of salt available at Government Golahs :

(c) any other matter which, in the opinion of the Salt Commissioner, is relevant for the purpose."

(ii) In clause (c), for the portion beginning with the words "The Importer shall" and ending with the words "approved by the Salt Commissioner", the following shall be substituted namely :—

"The importers shall observe the provisions of the rules regarding the administration of the Salkia Salt Golahs in respect of storage and removal of salt in reserve stock."

(b) In paragraph 4, after the sub-paragraph beginning with the words "The quantity of salt stored" and ending with the words "authorised by him in this behalf", the following sub-paragraph shall be inserted namely :—

"The reserve stock shall normally be kept for a period of one year but releases may be made from the storage "on first come first served" basis as soon as the total reserve stock crosses the maximum limit prescribed by the Salt Commissioner, from time to time. The period may, however, be extended by the Salt Commissioner, if the situation so warrants.

[F. No. 05018/3/71-Salt]

K. K. JASWAL, Dy. Secy.

(भारी उद्योग विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1979

का० आ० 873—विकास परिषद् (कार्यविधिक) नियम, 1952 के नियम 2,4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) के आदेश सं० का०आ० 3149 दिनांक 9 अगस्त, 1976, समय-समय पर यथासंशोधित, द्वारा नियुक्त किए गए सदस्यों, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों को तुरन्त प्रभाव से दो वर्ष की अवधि के लिए मशीनी औजारों के निर्माण अथवा उत्पादन रत अनुसूचित उद्योगों की विकास परिषद् का सदस्य नियुक्त करती है।

मशीनी औजारों की विकास परिषद्

1	2	3
1	श्री वी० कृष्णमूर्ति, सचिव, भारी उद्योग विभाग	अध्यक्ष
2	श्री ए०एफ० कुटो, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग	सदस्य-सचिव
3	श्री पी० राजगोपालन, अपर महानिदेशक, आयुद्ध कारखाना महानिदेशालय, कलकत्ता	सदस्य
4	श्री बी० रामचन्द्रा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एच० एम० टी० लिमिटेड, बंगलौर	सदस्य
5	श्री जी० पी० वारियर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	सदस्य
6	श्री जी० रमण, अपर सलाहकार (यांत्रिक तथा धातुकर्मिक इंजीनियरी के प्रभारी), लघु उद्योग विकास आयुक्त का कार्यालय	सदस्य
7	श्री ए० बी० मलिक, विकास अधिकारी (एस० जी०) तकनीकी विकास का महानिदेशालय	सदस्य
8	श्री एस० सी० ढींगरा, मुख्य (इंजीनियरी), योजना आयोग	सदस्य
9	श्री आर० जी० कम्बले, पी० एम० ओ०, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
10	श्री वी० एस० वर्मा, प्रभारी उप महाप्रबंधक, (एच०एम०टी०पी०), हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची	सदस्य
11	डा० सी०ए० फालनीकर, अध्यक्ष, आई० एम० टी० एम० ए०	सदस्य
12	श्री एम० ई० विश्वेस्वरन, निदेशक, सी० एम० टी० आई०, बंगलौर	सदस्य
13	औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो का एक प्रतिनिधि	सदस्य
14	श्री आर० जे० मेहता, इंजीनियरिंग मजदूर सभा, केनेडी हाउस, केनेडी बिल्डिंग, बम्बई	सदस्य
15	वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधि (आई०डी०बी०आई० द्वारा नामित किया जाना है)	

[सं० 19-7/78-एम०टी०]

ए० एफ० कुटो, संयुक्त सचिव

(Department of Heavy Industry)

ORDER

New Delhi, the 23rd February, 1979

S.O.873 :—In exercise of powers conferred by Section 6 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with Rules 2,4 and 5 of the Development Council (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints, for a period of two years with immediate effect, the following persons to be members of the Development Council for the Scheduled Industries engaged in the manufacture or production of Machine Tools, in place of the members appointed under the late Ministry of Industry & Civil Supplies (Department of Heavy Industry) order No. SO 3149 dated 9th August 1976, as amended from time to time, whose tenure of office has expired

DEVELOPMENT COUNCIL FOR MACHINE TOOLS

1	2	3
1.	Shri V. Krishnamurthy, Secretary, Deptt. of Heavy Industry	Chairman
2.	Shri A.F. Gouto, Joint Secretary Deptt. of Heavy Industry	Member-Secretary
3.	Shri P. Rajagopalan, Addl. Dir. General, Director General of Ordnance Factories, Calcutta	Member
4.	Shri B.Ramachandra, Chairman and Managing Director, H.M.T. Ltd., Bangalore	,,
5.	Shri G.P. Warrior, Chairman and Managing Director B.H.E.L.	,,
6.	Shri G. Raman Indl. Adviser (Incharge of Mechanical & Metallurgical Eng.). DC (SSI)	,,
7.	Shri A.B. Malik, Development Officer, (SG) DGTD.	,,
8.	Shri S.C. Dhingra, Chief (Engg.) Planning Commission.	,,

1	2	3
9.	Shri R.G. Kumble, PSO, Deptt. of Science & Technology	Member
10.	Shri V.S. Verma, Deputy General Manager, In-charge (HMTP) HEC Ltd. Ranchi	"
11.	Dr. C.A. Phalnikar, President, IMTMA. Bombay	"
12.	Sari M.E. Visveswaran, Director CMTI, Bangalore	"
13.	A representative of the Bureau of Industrial Costs & Prices	"
14.	Shri Raj Mehta, Engineering Mazdoor Sabha, Kannedy House, Kannedy Building, Bombay.	"
15.	Representative of Financial Institutions (to be nominated by IDBI).	

[No. 19-7/78-MT]
A. F. COUTO, Jt. Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1979

शुद्धि पत्र

का० आ० 874.—भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 9 नवम्बर, 1978, के पृष्ठ 1395 से 1402 पर प्रकाशित, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 638 (अ), तारीख 9 नवम्बर, 1978 में :—

(1) पृष्ठ 1395 पर— अधिसूचना में "ख" तथा "2" में, "4801 एकड़" के स्थान पर "4801. 333 एकड़" पढ़िए।

(2) पृष्ठ 1396 पर (i) बुखसा ग्राम में अर्जित प्लाटों की संख्या में,—

"50/1 से 506" के स्थान पर, "50/1 से 50/6" पढ़िऐ ;

"357/1, 356/2" के स्थान पर, "356/1, 356/2" पढ़िऐ ;

"396/1, 397/2" के स्थान पर, "397/1, 397/2" पढ़िऐ ;

"430/1 से 435/4" के स्थान पर, "435/1 से 435/4" पढ़िऐ ;

"444/1, 444/4" के स्थान पर, "444/1 से 444/4" पढ़िए ;

"480/1 से 480/6" के स्थान पर, "480/1 से 480/5" पढ़िऐ।

(ii) बारकट्टा ग्राम में अर्जित प्लाटों की संख्या में,—
"191 और 192/1 के (पी)" के स्थान पर, "191 और 192/1 के (पी)" पढ़िए ;

(iii) जटराज ग्राम में अर्जित प्लाटों की संख्या में,—
असर्वेक्षित क्षेत्र को अर्जित किया जाना है" के स्थान पर, "असर्वेक्षित क्षेत्र अर्जित किया गया है"।

(4) पृष्ठ 1397 पर—(i) प्रथम पंक्ति में, "सीमा व वर्णन" के स्थान पर, "सीमा वर्णन" पढ़िए ;
क—ख रेखा में,—

(ii) "499, 403/1" के स्थान पर, "499, 501, 502, 495, 447, 445/2, 444, 443, 413, 410, 409, 403/1," पढ़िए।

पृष्ठ 1397 पर— ख—ग रेखा में, पंक्ति 9 में,—
"37/1 के एम" के स्थान पर, "371/ के एच" पढ़िए।
ग—ख रेखा में, पंक्ति 2 में,—
"192/1—ठ" के स्थान पर, "192/1" पढ़िए।

(5) पृष्ठ 1397 पर—अनुसूची "ख" में,—

(i) स्तम्भ 7 के शीर्ष में, "अधिकारी भूमि" के स्थान पर, "अभिधारी भूमि" पढ़िए ;

(ii) स्तंभ 2 क्रम सं० 3 पर "पाडनिया" के स्थान पर, "पडानिया" पढ़िए; तथा

(iii) स्तंभ 2 क्रम सं० 7 पर "पंडी पानी" के स्थान पर, "पाड़ीपानी" पढ़िए।

(6) पृष्ठ 1398—पर गियोरा ग्राम में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या में,—

(i) "1580 में 1582" के स्थान पर, "1580 से 1582" पढ़िए ;

(ii) "1615" के स्थान पर, "1615 पी" पढ़िए ;
"1616—1627" के स्थान पर, "1616 से 1627" पढ़िए ;

" "सोनपुरी ग्राम में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या में,
"83/85" के स्थान पर "83 से 85" पढ़िए।

(7) पृष्ठ 1399 पर—पाड़निया ग्राम में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या में,—
"137/22" के स्थान पर "137/2" पढ़िए ;

" "अथोरा ग्राम में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या" के स्थान पर, "अथोरा ग्राम में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या पढ़िए ;

" पाली ग्राम में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या में,—
"230/1, 230/4" के स्थान पर, "230/1 से 230/4" पढ़िए।

(8) पृष्ठ 1401—पर दुरपा ग्राम में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या में,—

(i) "802 804" के स्थान पर "802 से 804" पढ़िए ;

(ii) 877/1 से 877/5" के स्थान पर "877/1 से 877/5" पढ़िए ;

(iii) "1007 से 1001" के स्थान पर "1007 से 1009" पढ़िए ;

पृष्ठ 1401 पर— नरईबाद ग्राम में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या में,—

(i) "170/1 से 173/5" के स्थान पर, "170/1 से 170/3" पढ़िए ;

(ii) "221/2" के स्थान पर, "221/2 पी" पढ़िए ,

(iii) "519 से 524 से 525/1" के स्थान पर, 519 से 524, 525/1" पढ़िए ;

" बरपाली ग्राम में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या में,—
"499, 508" के स्थान पर, "499 से 508" पढ़िए।

पृष्ठ 1402 पर— "828 से 631" के स्थान पर, "828 से 631" पढ़िए ;

"दुल्लापुर ग्राम में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या में,—

"27/5 पी, 27" के स्थान पर, "27/5 पी, 28" पढ़िए;

पृष्ठ 1402 पर—सीमा वर्णन रेखा ड—ठ में,—

(i) "21-9-81" के स्थान पर, "21-9-8/1" पढ़िए ;

(ii) "पचीरा ग्राम के प्लाट सं० 438/2, 353 और 352-351—350 से होकर गुजरती है" के स्थान पर, "470, 469, 467, 466, 444, 443/2, 438/2, 353 और 352—351—350 से होकर गुजरती है" पढ़िए ;

रेखा ठ—ट ग्राम नराइबाद की प्लाट सं० ——423/1 और 412/1 से होकर गुजरती है" के स्थान पर, "423/1 और 417/1 से गुजरती है" पढ़िए ।

"ट—" के स्थान पर "ट—ड़ा"; पढ़िए।

[फा० सं० 19 (31)/78-सी० एल०]

एस० आर० ए० रिजवी, निदेशक

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 22nd February, 1979

CORRIGENDA

S.O. 874.—In the notification of Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 638(E) dated the 9th November, 1978, published at pages 1395 to 1404/4 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 9th November 1978.

(1) At page 1402
For number of the notification read "S.O. 638(E)";

(2) At page 1403
in column 1, line 4 for "soid Schedule" read "said Schedule" ;

In Schedule A.

(a) under the heading "Plot numbers acquired in village Durpa" in Column 2, for "594/1" read "459/1" ;

(b) under the heading "Plot numbers acquired in village Jatraj"—

for "Un-surveyed Area is to be acquired" read "Un-surveyed Area is acquired" ;

(3) At page 1404
In Schedule "B", in the Table :—

(a) against serial No. 5, under the heading "Govt. Land", for "7.991" read "7.911",

(b) against serial No. 9, under the heading "name of the village" for "Khairbhaqna" read "Khairbhaona";

(4) At page 1404/1

(a) under the heading "Plot numbers acquired in village Geora"—

(i) for "514/1, 514/1" read "514/1, 514/2";

(i) for "234 to 245, 247" read "234 to 245, 246,

(b) under the heading "Plot numbers acquired in village Sonpuri", in column 2,

(i) for "234 to 245, 247" read "234 to 245, 246, 247" ;

(ii) for "350 to 252" read 250 to 252" ;

(iii) omit "323 2" ;

(iv) for "350/3 to 350/6" read "350/1 to 350/6";

(c) under the heading "Plot numbers acquired in village Pandania"—
for "766/1" read "676/1" ;

(5) At page 1404/2
under the heading "Plot numbers acquired in village Churel" in column 2, for "58P" read "98P" ;

(6) At page 1404/3

(a) under the heading "Plot numbers acquired in village Durpa" ;

(i) for "266" read "265" ;

(ii) for "842 to 84" read "842 to 849" ;

(b) under the heading "Plot numbers acquired in village Naraibad"—

(i) for "119P, 144/1" read 119P, 120P, 144/1P" ;

(ii) for "145/2P, 145/2P" read "145/1P, 145/2P";

(iii) for "148/1" read "148/1, 148/2" .

(iv) for "203/4 203/2" read "203/1, 203/2" ;

(v) for "336/1 to 326/3" read "326/1 to 326/3";

(c) (i) under the heading "Plot numbers acquired in village Barpali" —

for "402/1, to 412/5" read "402/1 to 402/5";

(ii) for "516, to 517" read "513 to 517";

(7) At page 1404/4

(a) in column 1, —

(i) Line 2 omit "617".

(ii) in line 22, for "21-1-9-1-8/1" read "21-9-8/1";

(iii) In line 25 and 26,
for "1538/1-2, 3-4" read "1583/1-2-3-4" ;

(b) On column 2, in line 20.
for "1182/1" read "1182/11"

[F. No. 19(31)/78-CL]

S. R. A. RIZVI, Director

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1979

का० आ० 875.—अतः केन्द्रीय सरकार ने खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले खाद्यान्नों के क्रय, भण्डारकरण, संचलन, परिवहन, वितरण तथा विक्रय के कृत्यों का पालन करना बंद कर दिया है जोकि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 13 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के कृत्य हैं ।

और यतः खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों में कार्य कर रहे और उपरिवर्णित कृत्यों के पालन में लगे निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार के तारीख 16 अप्रैल, 1971 के परिपत्र के प्रत्युत्तर में उसमें विनिर्दिष्ट तारीख के अन्दर भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी न बनने के अपने आशय को उक्त अधिनियम की धारा 12ए की उपधारा (1) के पुस्तक द्वारा यथा अपेक्षित सूचना नहीं दी है।

अतः अब खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) यथा अवयत संशोधित की धारा 12 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करती है :—

क्रम संख्या	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	केन्द्रीय सरकार के अधीन किस पद पर स्थायी है	स्थानान्तरण के समय केन्द्रीय सरकार के किस पद पर थे।	भारतीय खाद्य निगम को स्थानान्तरण की तारीख
1	2	3	4	5
1.	श्री बसन्त नारायण माथुर	..	निरीक्षक	1-3-1969
2.	श्री सौदागर सिंह कैथ	सत्यापन निरीक्षक	गोदाम अधीक्षक	1-3-1969
3.	श्री आर० एल० शर्मा	गोदाम लिपिक	कनिष्ठ गोदामरक्षक	1-3-1969
4.	श्री बुखारी लाल	सिफटर	सिफटर	1-3-1969
5.	श्री शान्ताराम-ढोंडीराम तेलहुरे	तौल लिपिक	कनिष्ठ गोदाम रक्षक	1-3-1969

[फाइल संख्या-52/1/79 एफ० सी० III]

बख्शी राम, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 20th February, 1979

S.O. 875.—Whereas the Central Government has ceased to perform the functions of purchase, storage, movement, transport, distribution and sale of foodgrains done by the Department of Food, the Regional Directorates of Food, the Procurement Directors and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food which under Section 13 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) are the functions of the Food Corporation of India;

And whereas the following officers and employees serving in the Department of Food, the Regional Directorate of Food, the Procurement Directorates and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food and engaged in the performance of the functions mentioned above have not, in response to the Circular of the Central Government dated the 16th April, 1971 intimated, within the date specified therein, their intention of not becoming employees of the Food Corporation of India as required by the proviso to sub-Section (i) of Section 12A of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 12A of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) as amended upto date the Central Government hereby transfer the following officers and employees to the Food Corporation of India with effect from the date mentioned against each of them.

Sl. No.	Name of the Officer/ employees	Permanent post held under the Central Govt.	Post held under the Central Govt. at the time of transfer	Date of transfer to the F.C.I.
1	2	3	4	5
1.	Sh. Basant Narayan Mathur.	—	Inspector	1-3-69
2.	Sh. Sodagar Singh Kainth.	Verification Inspector	Godown Superintendent	1-3-69
3.	Sh. R.L. Sharma.	Godown Clerk	Junior Godown Keeper.	1-3-69
4.	Sh. Bukhari Lal.	Sifter	Sifter	1-3-69
5.	Sh. Shantaram Dhondiram Telhure.	Weighment Clerk	Jonior Godown Keeper	1-3-69

[No. 52/1/79-FC.III]

BAKHSHI RAM, Dy. Secy.

भाँवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1979

(व्यापार पोत)

का० आ० 876—भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन और संचार मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० आ० 3141 दिनांक 17 दिसम्बर, 1960 द्वारा पाल जहाजों को यथाप्रवृत्त व्यापार पोत अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 23 और 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कवरावली द्वीप में लक्षद्वीप पत्तन को, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उक्त अधिनियम के अधीन पाल जहाजों के लिए रजिस्ट्री पत्तन घोषित करती है और उक्त पत्तन पर, कवरावली द्वीप में लक्षद्वीप के पत्तन अधिकारी को पाल जहाजों का रजिस्ट्रार नियुक्त करती है।

[फ० सं० 5-एम० एस० आर० (29)/78-एम० सी०]

के० लाल, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 23rd February, 1979

(MERCHANT SHIPPING)

S.O. 876.—In exercise of the powers conferred by sections 23 and 24 of the Merchant Shipping, Act, 1958 (44 of 1958), as applied to sailing vessels by the notification of the Government of India in the late Ministry of Transport and Communications No. S.O. 3141, dated the 17th December 1960, the Central Government hereby declares the Port of Lakshadweep in the Kavaratti Island to be Port of Registry of Sailing Vessels, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette under the said Act and appoints the Port Officer Lakshadweep, Kavaratti Island to be the Registrar of Sailing Vessels at the said port.

[F. No. 5-MSR(29)/78-MA]

K. LALL, Under Secy.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1979

का० आ० 877—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय

सरकार इसके द्वारा केरल सरकार के श्रम तथा आवास विभाग के पुनर्वास निदेशक तथा पदेन संयुक्त सचिव को, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सहायक महा अभिरक्षक, निष्क्रान्त सम्पत्ति को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए, सहायक महा अभिरक्षक, निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करती है।

[सं०-1 (8)/विशेष सैल/79-एस० एस०-2(1)]

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 13th February, 1979

S.O. 877.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoints the Director of Rehabilitation and Ex-Officio Joint Secretary in the Labour and Housing Department, Government of Kerala, as Assistant Custodian General of Evacuee Property for the purpose of discharging the duties imposed on such Assistant Custodian General by or under the said Act with immediate effect.

[No. 1(8)/Spl. Cell/79-SS. II(I)]

का० आ० 878.—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा केरल राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को, उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त उनके अपने-अपने जिलों में निष्क्रान्त सम्पत्तियों के संबंध में, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उप अभिरक्षकों को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए, उप अभिरक्षक निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 1 (8)/विशेष सैल/ 79-एस एस-2 (3)]

S.O. 878.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoints all the District Collectors in the State of Kerala as Deputy Custodians of Evacuee Property in addition to their own duties, as District Collector for the purpose of discharging the duties imposed on such Deputy Custodians by or under the said Act in respect of evacuee properties in their respective Districts.

[No. 1(8)/Spl. Cell/79-SS. II(iii)]

का० आ० 879.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 14) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा, केरल राज्य के श्रम तथा आवास विभाग के पुनर्वास निदेशक तथा पदेन संयुक्त सचिव को, पुनर्वास निदेशक तथा पदेन संयुक्त सचिव के रूप में उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त, केरल राज्य में मुआवजा पूल के भाग की भूमि संपत्तियों के संबंध में, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बंदोबस्त आयुक्त को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए बंदोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० 1 (8) /विशेष सैल/79-एस एस 2 (4)]

S.O. 879.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Director of Rehabilitation and Ex-Officio, Joint Secretary to the Government of Kerala, Labour and Housing Department as Settlement Commissioner for the purpose of performing in addition to his own duties as Director of Rehabilitation and Ex-Officio Joint Secretary the functions assigned to a Settlement Commissioner by or under the said Act, in respect of the land properties forming part of the Compensation Pool within the State of Kerala.

[No. 1(8)/Spl. Cell/79-SS. II(iv)]

का० आ० 880.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा 4 तथा धारा 33 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी भी शक्ति का, केरल राज्य में मुआवजा पूल के भाग की भूमियों तथा सम्पत्तियों के संबंध में केरल सरकार के श्रम तथा आवास विभाग के सचिव द्वारा उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त भी प्रयोग किया जाएगा।

[सं०- 1 (8)/विशेष सैल/79-एस० एस० 2 (vi)]

दीना नाथ असीजा, संयुक्त निदेशक

S.O. 880.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby directs that any powers exercisable by it under sub-section (4) of Section 24 and Section 33 of the said Act shall be exercisable also by the Secretary in the Labour and Housing Department of the Government of Kerala in addition to his own duties, in respect of the lands and properties forming part of the Compensation Pool within that State of Kerala.

[No. 1(8)/Spl. Cell/79-SS. II(vi)]

D. N. ASIJA, Jt. Director

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1979

का० आ० 881.—निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 55 की उपधारा (3) द्वारा महा अधिक्षक के रूप में मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, इसके द्वारा इस विभाग की दिनांक 13 फरवरी, 1979 की अधिसूचना संख्या 1 (8)/विशेष सेल/79-एस० एस०-II(1) द्वारा केरल राज्य के लिए सहायक महा अभिरक्षक निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में नियुक्त केरल सरकार के श्रम तथा आवास विभाग के पुनर्वास निदेशक तथा पदेन संयुक्त सचिव को महा अभिरक्षक की निम्नलिखित शक्तियां सौंपता हूं :—

(i) अधिनियम की धारा 24 और 27 के अधीन शक्तियां।

(ii) अधिनियम की धारा 10 (2) (O) के अधीन किसी भी निष्क्रांत सम्पत्ति के हस्तान्तरण के अनुमोदन की शक्तियां।

(iii) निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन (केन्द्रीय) नियमावली, 1955 के नियम 30-क के अधीन मामलों के हस्तान्तरण की शक्तियां।

[सं० 1(8)/विशेष सैल/79-एस०एस०II (ii)]

New Delhi, the 13th February, 1979

S.O. 881.—In exercise of the powers conferred on me as Custodian General by Sub-Section (3) of Section 55 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), I hereby delegate to Director of Rehabilitation and Ex-Officio, Joint Secretary, Labour and Housing Department, Government of Kerala appointed as Assistant Custodian General of Evacuee Property for the State of Kerala vide this Department's notification No. 1(8)/Spl. Cell/79-SS. II(1) dated 13th February, 1979, the following powers of the Custodian General :—

(i) Powers under Section 24 and 27 of the Act.

(ii) Powers of approval of transfer of any evacuee property under Section 10(2)(O) of the Act.

(iii) Powers of transfer of cases under Rule 30-A of the Administration of Evacuee Property (Central) Rules, 1955.

[No. 1(8)/Spl. Cell./79-SS. II(ii)]

का० आ० 882.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त इसके द्वारा इस विभाग की दिनांक 13 फरवरी, 1979 की अधिसूचना सं०-1(8)/विशेष सैल/79-एस०एस०-II (iv) द्वारा बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त केरल सरकार के पुनर्वास निदेशक तथा पदेन संयुक्त सचिव को निम्न शक्तियां सौंपते हैं :—

(i) उक्त अधिनियम की धारा 23 के अधीन अपीलें सुनने की शक्तियां ।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 24 के अधीन पुनरीक्षण संबंधी सुनवाई की शक्तियां ।

(iii) उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन मामलों के हस्तान्तरण की शक्तियां ।

[सं० 1(8)/विशेष सैल/79-एस० एस०-II (v)]

कौशल कुमार, मुख्य बंदोबस्त आयुक्त ।

S.O. 882.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (2) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (Act No. 14 of 1954), the Chief Settlement Commissioner hereby delegates to Director of Rehabilitation and Ex-Officio Joint Secretary to Government of Kerala, appointed as Settlement Commissioner, vide this Department's Notification No. 1(8)/Spl. Cell/79-SS. II(iv) dated 13th February, 1979, the following powers :—

(i) Powers to hear appeals under Section 23 of the said Act.

(ii) Powers to hear revisions under Section 24 of the said Act.

(iii) Powers to transfer cases under Section 28 of the said Act.

[No. 1(8)/Spl. Cell/79-SS. II(v)]

KAUSHAL KUMAR, Chief Settlement Commissioner.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1979

का० आ० 883.—राष्ट्रपति, श्री एस० एन० मुखर्जी जो कि पश्चिम बंगाल उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य हैं तथा हाल में कलकत्ता में तीसरे अतिरिक्त विशेष न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर थे को 7-2-79 से अगला आदेश होने तक महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) कलकत्ता में प्रतिनियुक्ति पर सक्षम प्राधिकारी के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

[सं० 78 ई (ओ) II/25/10]

पी० एन० मोहिले, सचिव रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 21st February, 1979

S.O. 883.—The President is pleased to appoint Shri S. N. Mukherjee, a member of West Bengal Higher Judicial Service lately Judge, Calcutta 3rd Addl. Special Court, on deputation to Competent Authority on the Metropolitan Transport Project (Railways), Calcutta with effect from 7-2-79 until further orders

[No. 78E(O) II/25/10]

P. N. MOHILE, Secy. Railway Board & Ex-Officio Jt. Secy. to the Govt. of India.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1979

का० आ० 884.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है :

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री सी० एल० नरसिंह राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के प्रबंधतंत्र के लिए, 465-725 रु० के वेतनमान में लोको ड्राइवर डीजल और 575-840 रु० के वेतनमान में ज्येष्ठ ड्राइवर डीजल बीजी लोको के दो वर्तमान काडरों के स्थान पर लोको ड्राइवर और ज्येष्ठ लोको ड्राइवर के पदों को मिलाकर 465-725 रु० के वेतनमान में एक काडर बनाना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

[सं० एल-34011(11)/78-डी० 4 (ए)]

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 8th February, 1979

S.O. 884.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Visakhapatnam Port Trust Visakhapatnam and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri C. L. Narasimha Rao shall be the Presiding Officer with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the management of Visakhapatnam Port Trust are justified in amalgamating the posts of Loco Drivers and Senior Loco Drivers into one cadre having the scale of pay of Rs. 465-725 in place of

two existing cadres of Loco Drivers Diesel in the scale of Rs. 465-725 and Senior Driver Diesel B. G. Loco in the scale of of Rs. 575-840 ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?

[No. L-34011 (11)/78-D. IV (A)]

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1979

का० आ० 885.—मैसर्स इस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड की चापुई खास कोलियरी, डाकघर कालीपहाड़ी, जिला बर्दवान के प्रबंधतंत्र और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व कोलियरी मजदूर यूनियन (इंटक), डाकघर उखरा करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार को, जो उसे 17 फरवरी, 1979 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10क के अधीन)

पक्षकारों के नाम :

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : 1. श्री के० पी० सिंह, उप-क्षेत्र प्रबंधक, रतिबती उप-क्षेत्र, इस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड.

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : 1. श्री सी० एस० बनर्जी, संयुक्त महामंत्री कोलियरी मजदूर यूनियन (इंटक)

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री बी० सिन्हा सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), 19/1 उपकार गार्डन, आसन सोल के मध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है :—

1. विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय : "क्या इस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड की चापुई खास कोलियरी डाकघर-कालीपहाड़ी जिला बर्दवान के प्रबन्धतंत्र की अनुसूची में दिए गए 28 कर्मकारों को 6.3.77 (रविवार) को जो कि ऐसे कर्मकारों के लिए सामान्य कार्यदिवस था और साथ ही कोलियरी में होली उत्सव होने के कारण सवैतनिक छुट्टी का दिन था, नियोजित न करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

संलग्न अनुसूची

क्रमांक	नाम	पदनाम
1.	श्री सुधीर करमाकर	वैलडर
2.	" फकीर चन्द करमाकर	इलैक्ट्रिशियन
3.	" मानिक चन्द राय	वैलडर
4.	" कोएल गोप	लाइन मिस्त्री
5.	" इस्ताकिन मिया	सामान्य मजदूर
6.	" सुकुमार गोप	सामान्य मजदूर
7.	" कारुण्या बौरी	टी० आर० मजदूर
8.	" आर० विवाकरन	फिटर
9.	" सुबिमल गुहा	इलैक्ट्रिशियन
10.	" अरुण बौरी	टी० आर० मजदूर
11.	" बिजोय बौरी	लाइन मजदूर
12.	" मुकसूदन गोप	—यथोक्त—
13.	" शियूनाथ जसवारा	—यथोक्त—
14.	" संकर बौरी	लाइन मिस्त्री
15.	" राम रंजन राय	इलैक्ट्रिशियन
16.	" उमापदा राय	फिटर
17.	" खोकन करमाकर	सी० एल०/फिटर
18.	" सस्तीपदा डान	—यथोक्त—
19.	" छाकारी चटर्जी	—यथोक्त—
20.	" एस०के० अरनब	सी०एल०/इंचार्ज
21.	" उमापदा गोप	इलैक्ट्रिशियन
22.	" दिवाकर परमानिक	—यथोक्त—
23.	" सुधीर चन्द खान	—यथोक्त—
24.	" श्यामापदा डान	फिटर
25.	" बेचन एल० श्रीवास्तव	इलैक्ट्रिशियन
26.	" महादेव करमाकर	ब्लैकस्मिथ
27.	" डल्लु गोराय	—यथोक्त—
28.	" हीरा तिवारी	हैमर मैन

2. विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अंतर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है।

(क) मैसर्स इस्टर्न कोलफील्डस लि० की चापुई खास कोलियरी, डाकघर-कालीपहाड़ी जिला बर्दवान के नियोजक/प्रबन्धतन्त्र का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री के०पी० सिंह, उप-क्षेत्रीय प्रबन्धक, इस्टर्न कोलफील्डस लि० का रतिबति उप-क्षेत्र डाकघर-कालीपहाड़ी जिला बर्दवान।

(ख) कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री सी० एस० बनर्जी संयुक्त महामंत्री कोलियरी मजदूर संघ (इंटक), सिनेमा रोड डाकघर-उखरा, जिला बर्दवान।

3. कर्मकार का नाम यदि वह स्वयं विवाद में अंतर्वलित है या संघ का नाम यदि कोई हो जो प्रथमतः कर्मकार या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो : श्री सी० एस० बनर्जी, संयुक्त महा-मंत्री, कोलियरी मजदूर संघ (इंटक);

4. प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या : रजिस्टर में कर्मकारों की संख्या 1795.

5. विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या. 28 (उपरोक्त अनुसूची में दिए गए विवरण के अनुसार)।

मध्यस्थ अपना पंचाट सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिनों की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले	नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले
ह०/-(सी० एस० बनर्जी) 9.2.79	ह०/-(के०पी० सिंह) 9.2.79
संयुक्त महा-मंत्री	
कोलियरी मजदूर यूनियन	उप-क्षेत्रीय प्रबन्धक, ईस्टर्न कोलफील्डस लि० का रतिबति
(इंटक)	उप-क्षेत्र

साक्षी :

1—ह०/-अपठनीय
9.2.79

2—ह०/-अपठनीय
9.2.79

मैं उपरोक्त औद्योगिक विवाद में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूं।

ह०/-
(बी० सिंहा)
सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) आसनसोल
9.2.79

[सं० एल-19013/4/79-डी 4 (बी)]
नन्द लाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th February, 1979

S.O. 885.—Whereas an industrial dispute exists between the management of Chapui Khas Colliery, Post Office, Kalipahari, District Burdwan of Messrs Eastern Coalfields Limited and their workmen represented by the Colliery Mazdoor Union (INTUC), Post Office Ukhra.

And whereas, the said employers and their workmen have by a written agreement under sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government a copy of the said arbitration agreement;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of Section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said Agreement which was received by it on the 17th February, 1979.

AGREEMENT

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

Name of the parties

Representing Employers	i K. P. Singh, ıb-Area Managei, Ratibaty Sub-Area, Eastern Coafields Ltd.
Representing workmen :	Shri C. S. Banerjee, Jt. General Secretary, Colliery Mazdoor Union (INTUC).

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri V. Sinha, Asstt. Labour Commissioner (Central), 19/1 Upcar Garden, Asansol.

(i) Specific matters in dispute : "Whether the action of the management of Chapui Khas Colliery, Post Office Kalipahari District Burdwan of Eastern Coalfields Limited is justified in not employing the 28 workmen mentioned in the Schedule, on 6-3-77 (Sunday) which was a normal working day for such workmen and also a paid holiday on account of Holi festival in the colliery. If not, wrat relief the workmen concerned are entitled to ?"

SCHEDULE APPENDED

Sl. No.	Name	Designation
1.	Sri Sudhir Karmakar	Welder
2.	Sri Fakir Ch. Karmkar	Elec.
3.	Sri Manik Ch. Roy	Welder
4.	Sri Koli Gopa	Line Mistry
5.	Sri Istakin Mia	Genl. Maz.
6.	Sri Sukumar Gope	—do—
7.	Sri Kamakhya Bouri	T.R. Mazdoor
8.	Sri R. Divakaran	Fitter
9.	Sri Subimal Guha	Electrician
10.	Sri Arun Bouri	T.R. Maz.
11.	Sri Bijoy Bouri	Line Mazdoor
12.	Sri Muksudan Gope	—do—
13.	Sri Shewnath Jaswara	—do—
14.	Sri Sankar Bouri	Line Mistry
15.	Sri Ram Ranjan Roy	Electrician
16.	Sri Umapada Roy	Fitter
17.	Sri Khokan Karmakar	C.L./Fitter
18.	Sri Sastipada Dawn	C.L./Fitter
19.	Sri Chhakari Chatterjee	—do—
20.	Sri S.K. Arnab	C.L./Incharge
21.	Sri Umapada Gope	Electrician
22.	Sri Dibakar Paramanki	—do—
23.	Sri Sudhir Ch. Khan	—do—
24.	Sri Shyamapada Dawn	Fitter
25.	Sri Bechan L. Srivastav	Electrician
26.	Sri Mahadeb Karmakar	Blacksmith
27.	Sri Dullu Gorai	—do—
28.	Sri Hira Tewari	Hammeraman

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved:

(a)	Representing employer/ management of chapui Khas colliery, P.O. Kalipahari, Dt. Burdwan of M/s. Eastern Coalfields Ltd.	Sri K.P. Singh, Sub-Area Manager, Ratibaty Sub-Area of Eastern Coalfields Ltd., P.O. Kalipahari, Dt. Burdwan.
(b)	Representing the workmen :	Sri C.S. Banerjee, Jt. General Secretary, Colliery Mazdoor Union (INTUC), Cinema Road, P.O. Ukhra Dt. Burdwan.
(iii)	Name of the workman in case he himself is involved in the dispute or the name of the union, if any, representing the workman or workman in question.	Sri C.S. Banerjee, Jt. General Secretary, Colliery Mazdoor Union (INTUC).

(iv)	Total number of workmen employed in the undertaking affected.	Total workmen on roll 1795.
(v)	Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute	28 (as per the details in the above schedule)

The arbitrator shall make his awards within a period of sixty days from the date of publication in the official gazette or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing.

Representing workmen	Representing Employer
Sd/-(C. S. Banerjee)	Sd/-(K. P Singh)
9-2-79.	9-2-79.
Jt. General Secretary	Sub-Area Manager
Colliery Mazdoor Union (INTUC)	Ratibaty Sub-Area
	Eastern Coalfields Limited

WITNESS

(1) Sd/-Illegible
9-2-79

(2) Sd/-Illegible
9-2-79

I agree to act as an arbitrator in the above Industrial dispute

Sd/-

V. SINHA, Asstt. Labour Commissioner
9-2-79
(Central) Asansol

[No. L-1903 (4)/79-D-IV (B)]
NAND LAL, Desk Officer.

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1979

का० आ० 886—केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबन्ध, जहां तक कि उसके अधीन न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम, 1950 द्वारा विहित प्रारूप X में मजदूरी रजिस्टर का रखा जाना अपेक्षित है, शिक्षा मंत्रालय के अधीन भारतीय तकनीकी संस्थान, कानपुर के उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, जिनके लिए उक्त अधिनियम के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत की गई हैं, किन्तु शर्त यह होगी कि ऐसे कर्मचारियों की विशिष्टियां, इससे उपाबद्ध अनुसूची में, संस्थान में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, रखी जाएंगी।

अनुसूची

भारतीय तकनीकी संस्थान, कानपुर

———मास के लिए वेतन पत्रक खण्ड———

फाइल सं०	पदधारी	मूल वेतन	मंहगाई भत्ता	नगर प्रतिकरात्मक भत्ता	मकान किराया भत्ता

एस पी पी/पी पी	एस पी ए	अन्तरिम राहत	अतिरिक्त महंगाई भत्ता	प्रकीर्ण

आय-कर	जीवन बीमा निगम प्रीमियम	एच आर/ एस आर	अंशदायी भविष्य निधि + जी आर	अनिवार्य निक्षेप

निधि से अग्रिम	कर्मचारी संघ अभिदाय	कुल वेतन	कुल वसूलियां	शुद्ध संदेय

हस्ताक्षर

[सं० एस 32012(10)/76 डब्ल्यू सी (एम डब्ल्यू)]
अशोक नारायण, उप सचिव

New Delhi, the 26th February, 1979

S.O. 886.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) the Central Government hereby directs that, for a period of five years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the provision of sub-section (1) of section 18 of the said Act, in so far as it requires a register of wages to be maintained in the prescribed form, namely form X as prescribed by the Minimum Wages (Central) Rules, 1950, shall not apply in relation to the employees of the Indian Institute of Technology, Kanpur under the Ministry of Education for whom minimum rates of wages have been fixed under the said Act, subject to the condition that particulars of such employers shall be maintained in the Schedule annexed hereto in accordance with the procedure prevalent in the Institute.

SCHEDULE

Indian Institute of Technology Kanpur
Payroll For the Month of
Division

File No.	Incumbent	BP	DA	CCA

HRA	SPP/PP	SPA	INT.	RLF	AD.DA

Misc.	Income-Tax	LIC Premium	HR/SR	CPF—GR

Compulsory Deposit	Fund Advance	Karmchari Sangh Subscriptions	Gross Salary	Total Recoveries	Net Payable

Signature

[No. S. 32012 (10)/76-WC (MW)
ASHOK NARAYAN, Dy. Secy.

New Delhi, the 26th February, 1979

S.O. 887.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1 Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management

of Digwadih Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company, Post Office Jamadoba, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th February, 1979.

[No. L-20012/46/76-D. III (A)]

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 1, DHANBAD.

In the matter of a reference Under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 59 of 1977

PARTIES :

Employers in relation to the management of Digwadih Colliery of M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd., P. O. Jamadoba, Dist. Dhanbad

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers : Shri S. S. Mukherjee, Advocate

For the Workmen : None.

State : Bihar Industry : Coal.

Dhanbad, dated, the 5th February, 1979

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide it's Order No. L-20012/46/76-D-III(A), dated 10-5-1976 for the adjudication of the following industrial dispute :

"(1) Whether the action of the management of Digwadih Colliery of M/s. Tata Iron and Steel Company Ltd. Post Office Jamadoba, District Dhanbad in placing Shri Sitaram Barai under suspension for ten days with effect from 8-12-1975 on account of alleged unauthorised occupation of company's quarter is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?

(2) Whether the action of the management of Digwadih Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post Office Jamadoba, District Dhanbad, in dismissing Shri Sitaram Barai, Miner with effect from 18th December, 1975 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

2. The parties have filed a settlement. The terms of the settlement are verified. The settlement appears to be fair and proper. Award is given in terms of the settlement which shall form part of the award.

S. N. JOHRI, Presiding Office

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT No. I, DHANBAD

Reference No. 59 of 1977

Employers in relation to the Management of Digwadih Colliery of M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd., P. O. Jamadoba, Dist. Dhanbad.

AND

Their Workmen

The parties above named beg to submit as under :

That without prejudice to the respective contentions of the parties contained in their written statements, the dispute mentioned in the schedule of the reference has been amicably settled on the following terms :—

(i) That Sri Sitarma Barai, the workmen concerned in the present reference will be re-employed in his original post of a shifter.

(ii) That Sri Sitaram Barai will be treated as a fresh entrant, and will be placed in the Category on the last rate of wages drawn by him.

(iii) That Sri Sitaram Barai will not be entitled to his wages or any other compensation from the date of his dismissal namely 18-12-75 till he joins his appointment.

(iv) That Sri Sitaram Barai will report for his duty within seven days from the date of the Award of Hon'ble Tribunal in terms of the settlement.

(v) That the parties will bear their respective cost of this proceeding.

That the above terms of settlement finally resolved the disputes pending before the Honourable Tribunal and there remains no further disputes which needs any adjudication.

It is, therefore, hereby prayed that the above terms of settlement may kindly be accepted and award be passed in terms thereof.

For Workmen For Employers

1. Bejrangi Singh,
Secretary,
R. C. M. S. Digwadih Branch.

2. Sri Sitaram Barai,
(Concerned workman).

S. S. MUKHERJEE, Advocate, Dhanbad.

[No. L-20012/46/76-D. III (A)]

S.O. 888.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Coal Washery, Jamadoba, of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post Office Jamadoba, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th February, 1979.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT DHANBAD.

In the matter of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 94 of 1977.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Central Coal Washery, Jamadoba of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post Office Jamadoba, District Dhanbad.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

For the Workmen.—Shri S. Bose, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad.

State : Bihar. Industry : Coal.

Dhanbad, dated, the 7th February, 1979.

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide its order No. L-20012/143/77-D. III(A) dated, the 13th December, 1977, for the adjudication

of the following industrial dispute with respect to the workmen enlisted in Schedule I annexed to this Award:

"Whether the demand of the Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh for grant of higher category to the following workmen (See Anexure 1) of Central Coal Washery, Jamadoba, of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post Office Jamadoba, District Dhanbad is justified? If so, to what category are the said workmen entitled and from which date?"

2. It is not disputed that these twelve workmen have been paid category II Wages of daily rated workmen in the graduated scale of 5.35—0.12.68 as laid down in Wage Board recommendations and after the implementation of National Coal Wage Agreement of 1974, they are being paid in the corresponding revised scale of 10.44-0.26—13.00 in the same category. First three of them namely M/s. Etwari, Dukhran, and Mukhu Coupling branch shunting Porters (C.B.S.P.) who previously worked as miners at Jamadoba opted for this job in Central Coal Washery and were placed in category I, when Sri S. Das Gupta, Secretary of Colliery Mazdoor Sangh raised an industrial dispute for upgradation and ultimately vide settlement dated 16-11-71 they were placed in category II with effect from 1-12-1968.

3. Union's case is that looking to the tough nature of duties performed by them and the hazards involved, they should be equated with coupler/clipman/pointsman/signalman of Wage Board recommendations and accordingly should be paid category IV wages as revised by National Coal Wage Agreement The previous settlement of 1971 in respect of the three C.B.S.P. workman was superseded by the National Coal Wage Agreement hence there was no need to set it aside specifically and the dispute could therefore be raised with respect to them as well.

4. The case of the management is that so far as C.B.S.P. workmen are concerned no such dispute could be agitated unless the settlement of 1971 was set aside according to law. Reference to that extent is alleged to be illegal and void. On merits it is alleged that their nature of work cannot be equated with clipman and other of the Wage Board because these workmen under reference, work in Coal Washery on the Surface while those mentioned in the report work underground.

5. The settlement of 1971 decided the category in which the C.B.S.P. workmen should be placed and paid, while the National Coal Wage Agreement of 1974 only decided the corresponding revised scales of the old Wage Board scales. Thus the two agreements operated in two separate and distinct areas. They did not overlap each other and hence the National Coal Wage Agreement could not supersede, even by implication, the settlement of 1971 under which C.B.S.P. workmen were placed in category II. Admittedly no notice of termination of that settlement was given by the union u/s. 19 of the I.D. Act. That settlement therefore continues to remain binding between the parties by virtue of the provisions of S. 18 of I.D. Act and no industrial dispute can be raised till it is in force. The reference with respect to the C.B.S.P. workmen M/s. Etwari, Dukhan, and Mukhu is therefore illegal and not maintainable.

6. However the case of Shunters has to be judged independently. Sri D. C. D'Souza, Engineer incharge in the Coal Washery appeared in the witness box as M.W.1. He has confirmed the statements of workmen's witnesses by saying that C.B.S.P. workmen uncouple the wagons of raw coal and attach them to, or detach them back from the haulage rope outside the tippler. What they do outside is done by the shunters inside the tippler with the help of pinch bar and wooden blockers. Occasionally they help in closing the doors of the wagons which open outside downwards. He has rebutted the evidence of the workmen's witnesses in so far as they stated that they work as pointsman also. According to Sri D'Souza there is a Jamadar employed for that purpose. Workmen's witnesses admitted that there was a pointsman and two other persons are employed for closing the doors but they are not in a position to do the job by themselves and necessarily every time these shunters are required to help them. I am inclined to believe Sri D'Souza that such help is given only occasionally and therefore it cannot be said to be of much consequence.

7. Now the so proved nature of work cannot be equated and does not tally with any of the workmen of category II or Category III whose job description has been given in Appendix V of Vol. II of the Coal Wage Board recommendations at pages 43—46. Shunting Mazdoor No. 17 in Category II at page 44 of Vol. II is employed for moving railway wagons at colliery siding. Moving the wagons manually is very different from coupling or uncoupling them so far as the extent of skill is concerned. That is why the clipman or coupler who do the latter type of the job as per job description given at serial No. 3 on page 46 have been placed in category IV as against shunting mazdoors. So is the case with the trammers of Category III (Job description given at serial No. 18) on page 46 as compared to clipman or coupler of category IV. Thus the nature and extent of the skill involved in the work which is so proved to be done by these 9 shunters is such which can be equated only to the jobs of clipman/coupler of Category IV and to none else in categories II, or III. Hence the demand for category IV wages appears to be wholly justified.

8. The plea that Clipman/Pointsman/Coupler/Signalman have been placed in category IV only because they work underground is quite baseless. Categorisation was never done on that basis. Those who work underground get underground allowance as an additional benefit but otherwise they remain in the same category as those of their counterparts who work on the Surface.

9. It is therefore held that reference with respect to C.B.S.P. workmen is invalid in law. The 9 Shunters No. 4 to 12 of the Schedule of reference should be paid category IV wages as revised by the National Coal Wage Agreement, from the date on which the dispute was for the 1st time raised by the union before the management. All arrears on that account shall be paid to the concerned shunters. The management shall further pay Rs. 50 as costs to the union. Reference with respect to the three C.B.S.P. workmen is rejected as not maintainable being without jurisdiction. Award is given accordingly.

S. N. JOHRI, Presiding Officer.

ANNEXURE I

Sl. No.	Name of the worker	Designation/Present category.
1.	Shri Etwari	C.B.S.P./II
2.	Shri Dukhran	—do—
3.	Shri Mukhu	—do—
4.	Shri Ganpat	Shunter/II
5.	Shri Haru	—do—
6.	Shri Umrao	—do—
7.	Shri Deotadin	—do—
8.	Shri Haldhar	—do—
9.	Shri Harihar	—do—
10.	Shri Radhu	—do—
11.	Shri Hidyaat Mia	—do—
12.	Shri Seo Kumar Singh	—do—

[No. L-20012/143/77-D-III (A)]

S.O. 889.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ekta Engineering Workshop of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Kusunda (District Dhanbad) and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th February, 1979.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 1), DHANBAD

In the matter of a reference under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 3 of 1977

PARTIES : Employers in relation to Ekra Engineering Workshop of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P. O. Kusunda, Dist. Dhanbad.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers : Shri T. P. Choudhry, Advocate.

For the Workmen : Shri S. Bose, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad.

State : Bihar. Industry : Coal.

Dhanbad, dated, the 7th Febuary, 1979

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide its Order No. L-20012/116-76/D IIIA, dated 31-12-1976 for the adjudication of the following industrial dispute :—

"Whether the action of the management of Ekra Engineering Workshop of Messrs Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Kusunda (District Dhanbad) in refusing to take the following workmen in their employment is justified ? If not, to what relief are the said workmen entitled and from which date ?

(1) Sri Gajendra Prasad
(2) Sri Narendra Kumar
(3) Sri Deonandan Prasad
(4) Sri Laxi Kanta
(5) Sri Rajeshwar Prasad
(6) Sri Suresh Singh
(7) Sri Mulchand
(8) Sri Mahendra Paswan
(9) Sri Naushad Ali
(10) Sri Ganesh Chouhan
(11) Sri Ramsanehi Yadav
(12) Sri Bal M Paswan
(13) Sri Rajnet Rajbhar
(14) Sri Md. Jainul Abedin
(15) Sri Jagdhari Chouhan
(16) Sri Jhabulal Chouhan
(17) Sri Banshi Pd. Chouhan
(18) Sri Balji Ram
(19) Sri Kunjbihari Singh
(20) Sri Ram Pravesh Rai
(21) Sri Lakhan Sharma
(22) Sri Bishun Sao
(23) Sri Duryodhan Rewani
(24) Sri Ramchandra Ram
(25) Sri F. Fewani
(26) Sri Sib Dayal Gupta
(27) Sri Premnath
(28) Sri Ramphal Ram
(29) Sri Kewal Chouhan
(30) Sri Kamaldeo Yadav
(31) Umesh Singh."

2. The parties have filed a settlement. The terms of the settlement are verified. The settlement appears to be fair and proper. Award is given in terms of the settlement which shall form part of the award.

S. N. JOHRI, Presiding Officer

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT TRIBUNAL No. 1, DHANBAD IN THE MATTER OF REFERENCE No. 3/77

Employer in relation to Ekra Engineering Workshop of BCCL

AND

Their Workmen

Joint petition of compromise settlement in the above case, The humble petitioners, on behalf of the management and workmen concerned in the present dispute, beg to state :—

The pending hearing of the above reference the parties entered into negotiation for an amicable settlement of he dispute, and have been able to come to a settlement for a resolution of this dispute to the satisfaction of the parties, in the following terms :—

Terms of Settlement

(1) The parties agree that the workmen listed in the schedule of reference except who have already been working the different collieries of BCCL, shall be provided employment in permanent posts on the basis of their suitability.

NAMES

1. Sri Gajendra Prasad.
2. Sri Deonandan Prasad.
3. Sri Rajeshwar Prasad.
4. Sri Mulchand.
5. Sri Nausad Ali.
6. Sri Ramsanehi Yadav.
7. Sri Rajnet Rajbhar.
8. Sri Jagdhari Chouhan.
9. Sri Bansi Pd. Chouhan.
10. Sri Kunjbihari Singh.
11. Sri Lakhan Sharma.
12. Sri Duryodhan Rewani.
13. Sri F. Flewani.
14. Sri Premnath.
15. Shri Kewal Chouhan.
16. Sri Umesh Singh.
17. Sri Narendra Kumar.
18. Sri Laxmi Kanta.
19. Sri Suresh Singh.
20. Sri Mahendra Paswan.
21. Sri Ganesh Chouhan.
22. Sri Bal M. Paswan.
23. Sri Md. Jainul Abedin.
24. Sri Jhabulal Chouhan.
25. Sri Baiji Ram.
26. Sri Ram Parvesh Rai.
27. Sri Bishun Sao.
28. Sri Ramchandra Ram.
29. Sri Shib Dayal Gupta.
30. Sri Ramphal Ram.
31. Sri Kamal Deo Yadav.

(2) The parties agree that the workmen mentioned in para one shall undergo trade test to determine their suitability for particular posts.

(3) The parties agree that the workmen mentioned in para 1 (one) before being allowed to undergo trade test, shall produce their proofs of identity and date of birth, within 30 days of recording of the settlement before the Tribunal, failing which the claim of defaulting workmen for employ-

ment, shall stand forefeited. The parties agree that for correct identity of each and every worker the following procedures are to be followed immediatey after this settlement is executed.

(a) Photographs to be submitted by each scheduled workers after being attested.

(b) Each workmen is to swear affidavit on oath before the competent Court declaring his identity as correct and submit the said affidavit to the General Managet, Bhagaband Area.

(c) Village Mukhia Certificate in support of his identity to be submitted to the General Manager, Bhagaband Area.

(4) The parties agree that in case the identity of any such workers listed in the schedule under reference is disputed and it is proved that the person taken is not genuine one, his name will be removed from the rolls of the company immediately.

(5) That the parties agree to get age of each and every concerned workmen examined, assessed and determined by the General Manager, Bhagaband Area and determined age after examination will be acceped by both the parties and the decision of the Medical Board in regard to determination of age will be binding on both the parties and can not be a matter of dispute in future.

(6) The parties agree that the workmen concerned shall join the post offered to them on the basis of their determined suitability in any colliery or establishment of BCCI.

(7) The parties agree that the date of appointment of all the workmen concerned in this dispute shall be counted from the date of joining their duties irrespective of collieries and units.

(8) The petitioners pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept the compromise petition and terms of settlement as fair and reasonable and may be pleased to pass award in terms thereof.

(9) That 24 of the concerned persons signed this compromise in token of having accepted the contents thereof after fully understanding the same. Of the rest some are reported to be working in Bokaro Steel City while other are not locally available. The parties agreed that those persons will also be absorbed according to the terms and conditions aforesaid as and if and when they turn up within a period of 30 days for which the Branch Secretary will take proper steps to inform them and undergo trade test, medical examination and comply the other conditions.

For the Employers

(R. N. Mishra)
General Manager
Bhagaband Area
BCCL

(S. K. Mishra)
Personnel Manager
Bhagaband Area
BCCL

for the workmen

1. (Gajendra Prasad)
2. (Narandra Kumar)
3. (Deonandan Prasad)—Absent
4. (Laxmi Kamta)—Absent
5. (Rajeshwar Prasad)
6. (Suresh Singh)
7. (Mulchand)—Absent
8. (Mahendra Paswan)
9. (Nausad Ali)
10. (Ganesh Chouhan)
11. (Ramsanehi Yadav)
12. (Bal M. Paswan)
13. (Rajnet Rajbhar)
14. (Md. Jainul Abedin)
15. (Jagdhari Chouhan)
16. (Jhabulal Chouhan)
17. (Bansi Pd. Chouhan)
18. (Balji Ram)
19. (Kunjbihari Singh)
20. (Ram Pravesh Rai)—Absent
21. (Lakhan Sharma)
22. (Bishun Sao)
23. (Duryodhan Rawani)
24. (Ramchandra Ram)
25. (Shiv Dayal Gupta)
26. (F. Fewani)
27. (Premnath)
28. (Ramphal Ram)
29. (Kewal Chouhan)—Absent
30. (Kamaldeo Yadav)—Absent
31. (Umesh Singh)

Witnesses :—

1. (Noor Mohammad Ansari)
2. (Ravindra)

[No. L-20012/116/76-D. III(A)]

S.O. 890.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Katras Choitodih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Katrasgarh, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th February, 1979.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 73 of 1977

PARTIES :

Employers in relation to the Katras Choitodih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Katrasgarh, (Dhanbad).

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers : Shri T. P. Choudhury, Advocate

For the Workmen : Shri Bishan Das Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union, Dhanbad.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, dated 8th February, 1979

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide it's Order No. L-20012/21/77-DII(A) dated, the 19th May, 1977 for the adjudication of the following industrial dispute :

"Whether the action of the management of Katras Choitodih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited Post Office Katrasgarh, District Dhanbad in stopping the work of Sarva Shri Rajkumar Ram, Bikram Das, Sukhdeo Prasad, Tarhi Prasad, Jageswar Prasad, Bideshi Bhuia and Bundel Bhuia with effect from 16th August, 1976 is justified ? If not, to what relief are the said workmen entitled ?"

2. The parties have filed a settlement. The terms of the settlement are verified. The settlement appears to be fair and proper. Award is given in terms of the settlement which shall form part of the award.

S. N. JOHRI, Presiding Officer.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT DHANBAD

Ref. No. 73 of 1977

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Katras Choitodih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited.

AND

Their Workmen

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Katras Choitodih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, P. O. Katrasgarh, Distt. Dhanbad in stopping the work of Sarvashri Rajkumar Ram, Bikram Das, Sukhdeo Prasad, Tarhi Prasad Jageshwar Prasad, Bideshi Bhuia and Bundel Bhuia with effect from 16th August, 1976 is justified ? If not, to what relief are the said workmen entitled ?"

(1) That the parties in the meantime have discussed the matter and the same has been settled amicably. A copy of the settlement is marked Annexure 'A'.

(2) The dispute has, accordingly, been resolved to the satisfaction of both the parties.

It is therefore, prayed that the Hon'ble Tribunal may please hold the settlement as fair and reasonable and pass an award in terms thereof. And for this the petitioner shall ever pray.

For Management :

Sd/-
1. (R. K. CHOUDHARY)
Dy. Personnel Manager,
BCCL, Katras Area

Sd/-
2. (V. R. SINGH)
Sr. Personnel Officer,
BCCL, Katras Area.
KATRAS AREA.

For Workmen :

Sd/-
1. (BARHAN DAS, Secy.
Bihar Colliery Kamgar Union.
East Katras Zone,
P. O. Katrasgarh (DHANBAD).

Dated the 8th day of Feb. '79.

BHARAT COKING COAL LIMITED

(A Subsidiary of Coal India Limited)

Katras Area No. IV, P. O. Sijua (Dhanbad)

ANNEXURE 'A'

MEMORANDUM OF SETTLEMENT UNDER RULE 58(4) OF THE INDUSTRIAL DISPUTES (CENTRAL) RULE, 1957

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

NAME OF PARTIES :

Representing Management :

Sri. R. K. Choudhary,
Dy. Personnel Manager,
BCCL, Katras Area.

2. Sri. V. R. Singh,
Sr. Personnel Officer,
BCCL, Katras Area.

Representing the Workmen :

1. Sri Barhan Das,
Secretary,
Bihar Colliery Kamgar Union, East Katras Zone,
P. O. Katrasgarh,
Distt. Dhanbad.

SHORT RECITAL OF THE CASE

The Government of India, Ministry of Labour, vide order No. L-20012/21/77-D. IIIA, dated 19th May, 1977 referred the following dispute for adjudication to the Hon'ble Central Government Industrial Tribunal No. 1 at Dhanbad constituted under section 7A of the Industrial Disputes Act, 1947. The reference is numbered as Ref. No. 73 of 1977.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Katras Choitodih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, P. O. Katrasgarh, Distt. Dhanbad in stopping the work of Sarvashri Rajkumar Ram, Bikram Das, Sukhdeo Prasad, Tarhi Prasad, Jageshwar Prasad, Bideshi Bhuia and Bundel Bhuia with effect from 16th August, 1976 is justified ? If not, to what relief are the said workmen entitled ?"

Subsequent to the reference of the dispute, the matter has been discussed by and between the parties with a view to arrive at an amicable settlement. After discussion on several dates, it was agreed to resolve the dispute on the following terms and conditions :

1. That at the request of the sponsoring union namely, Bihar Colliery Kamgar Union, the Employers have since considered the matter afresh and have agreed to re-appoint all the seven concerned persons S/Shri Rajkumar Ram, Bikram Das, Sukhdeo Prasad, Tarhi Prasad, Jageshwar Prasad, Bideshi Bhuia and Bundel Bhuia as miners/loaders on permanent roll with immediate effect under the rules and regulation of the Company.

2. That it is agreed by the parties that due to typographical error, the name of Sri Tori Prasad has been typed as Tarhi Prasad in the Schedule. Sri Tarhi Prasad and Tori Parsad is one and the same person and thus it is agreed by the parties that his name will be corrected and read as Tori Prasad instead of Tarhi Prasad.

3. That it is also agreed by the parties that since the seven concerned workmen have worked interimittently only for a few months, the past service will not be considered for any purpose whatsoever.

4. That it is further agreed by the parties that the seven concerned persons will not also claim for their back wages etc. arising out of their stoppages.

5. That it is agreed by the parties that the management will be at liberty to utilize their services as maindrivers as and when required and the concerned person will not have any objection while performing the job of maindrivers.

6. That it is agreed by the parties that the seven persons will report for duty within 7 days from the date of signing of this settlement, failing which they will lose their claim for employment.

7. That it is agreed by the parties that this settlement finally resolves the entire dispute arising out of the stoppage from work of the seven persons whose names are mentioned in the schedule and the parties shall have no other claim in that connection, against each other.

8. That it is further agreed by the parties that a copy of this settlement be endorsed to A.L.C. (C), Dhanbad and other authorities as per Rule 58 (4) of the Industrial Dispute (C), Rule, 1957.

The dispute is fully and finally resolved accordingly.

SIGNATURES :

for Management :

Sd/-
1. (R. K. Choudhary)
Dy. Personnel Manager.
Katras Area.

Sd/-
2. (V. R. Singh)
Sr. Personnel Officer,
Katras Area.

for Workmen :

Sd/-
1. (Barhan Das)
Secretary,
Bihar Colliery Kamgar Union, East Katras Zone,
P.O. Katrasgarh, Distt. Dhanbad.

WITNESSES :

1. Sd/- illegible
2. Sd/- illegible

[No. L-20012/21/77-D. III(A)]

S.O. 891.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Dobari Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Jealgora, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th February, 1979.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 17 of 1978

PARTIES : Employers in relation to the management of Dobari Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Jealgora, District Dhanbad

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers : Shri T. P. Choudhry, Advocate.

For the Workmen : Shri B. Joshi, Advocate.

State : Bihar Industry : Coal

Dhanbad, dated the 8th February, 1979

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide its Order No. L-20012/115/77-D-III(A), dated, the 28th July, 1978 for the adjudication of the following industrial dispute :

"Whether the action of the management of Dobari Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Jealgora, District Dhanbad in dismissing from service Shri Raghupati Yadav, Night Guard, with effect from the 30th June, 1976, is justified ? If not to what relief is the said workmen entitled ?"

2. The parties have filed a settlement. The terms of the settlement are verified. The settlement appears to be fair and proper. Award is given in terms of the settlement which shall form part of the award.

S. N. JOHRI, Presiding Officer

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 1 AT DHANBAD

Reference 17 of 1978

Employers in relation to the management of Dobari Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd.

AND

Their Workmen.

PETITION OF COMPROMISE :

The above reference has been settled between the parties on the following terms :—

1. That the concerned workman, Shri Raghupati Yadav, Night Guard who was dismissed from service with effect from 30-6-76 will be taken back with continuity in service with immediate effect at Dobari colliery.

2. Shri Yadav, however will not get any back wages for the period he remained idle from 30-6-76 till the date of his joining duty.

3. That the entire period of his absence will be treated as on Leave without pay and the period from 30-6-76 till the date of his joining shall count towards his gratuity.

That since the above terms are fair and reasonable the parties pray that the Hon'ble Tribunal will be pleased to give its award in terms of the above compromise.

For and On behalf of the Employers	For and On behalf of the Workman
Sd/-	Sd/-
J. R. Varman,	Shri B. Joshi,
Dy. Personnel Manager,	Advocate
Security Hqrs., Jealgora.	T. I. of the concerned workman.
	1. Shri Raghupati Yadav,
Sd/-	
B. Prasad,	
Sr. Personnel Officer,	
Security Hqrs., Jealgora.	

Dated : the 8th February, 1979.

[No. L-20012/115/77-D. III (A)]

S.O. 892.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Damoda Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Karmatand, Giridih and their workmen, which was received by the Central Government on the 22nd February, 1979.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 55 of 1977

PARTIES : Employers in relation to the management of Damoda Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, P.O. Karmatand, Giridih.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers : Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen : Shri S. Bose, Secretary, Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad.

State : Bihar Industry : Coal.

Dhanbad, dated the 7th February, 1979.

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide it's Order No. L-20012|193|75|D-III(A), dated the 21st February, 1976 for the adjudication of the following industrial dispute :—

"Whether the action of the management of Damoda Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, P.O. Karmatand via Mohuda (District Giridih) in not placing Shri N. D. Sharma as Head Fitter (Category VI) is justified ? If not, to what relief the workman is entitled and from what date ?"

2. The parties have filed a settlement. The terms of the settlement are verified. The settlement appears to be fair and proper. Award is given in terms of the settlement which shall form part of the award.

S. N. JOHRI, Presiding Officer

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL, TRIBUNAL NO. 1, AT DHANBAD

Reference No. 55 of 1977

Employers in relation to the management of Damuda colliery.

AND

Their Workmen.

PETITION FOR COMPROMISE.

The humble joint petition on behalf of the parties above named most respectfully sheweth :—

1. That without prejudice to the respective contentions of the parties contained in their respective written statements, the parties have amicably settled the disputes on the following terms :—

Terms of Settlement

1. (a) The management has promoted the concerned workman, Sri Nandeswar Sharma from category V Fitter to the equivalent post of Head Fitter of category VI with effect from 14-8-78.

(b) The management shall treat him as category VI Fitter from 1-5-1973 for the purpose of counting his seniority at the time of his promotion to the next higher post.

(c) Sri Nandeswar Sharma will not claim any difference of wages for the period of dispute i.e. from 1-5-73 till 14-8-78.

(d) Sri Nandeswar Sharma will not claim any amount in the form of differences in Bonus and allowances and privileges for the aforesaid period from 1-5-73 till 14-8-78.

2. That in view of the aforesaid settlement the industrial dispute under reference has been amicably resolved.

It is, therefore, humbly prayed that the Hon'ble Tribunal be graciously pleased to accept the compromise as fair and proper and be pleased to pass the award in terms of the settlement.

For the Workmen	For the Employers
Signature of the concerned workman	Signature of General Manager Area No. 1, Bharat Coking Coal Ltd.
Signature of Union's representative.	Signature of B. Joshi, Advocate

[No. L-20012/193/75-D. III (A)]

S. H. IYER, Desk Officer

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1979

का० आ० 893.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने तुनी टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-3-79 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं० 5-7/79-पी०एच०बी०]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 28th February, 1979

S.O. 893.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs hereby specifies 16-3-79 as the date on which the Measured Rates System will be introduced in Tuni Telephone Exchange, Andhra Pradesh Telecom. Circle.

[No. 5-7/79-PHB]

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1979

का. आ. 894.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने मधुरवाडा, सिमहाचलम, पेंडुरथी टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-3-79 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-7/79/पी. एच. बी.]

आर. सी. कटारिया, सहायक महानिदेशक,
(पी. एच. बी.)

New Delhi, the 2nd March, 1979

S.O. 894.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16-3-79 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Madhurawada, Simhachalam & Pendurthy Telephone Exchanges, Andhra Pradesh Telecom. Circle.

[No. 5-7/79-PHB]

R. C. KATARIA, Asstt. Director

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1978

का०आ० 895.—भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) के खण्ड 82-जे० द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा रेल दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) नियम, 1950 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को रेल दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) द्वितीय संशोधन नियम, 1978 कहा जाये।

(2) ये नियम सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. रेल दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) नियम, 1950 के नियम 6 के उपनियम (3) और (4) को निम्नलिखित उपनियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :

"(3) किसी चोट के संबंध में, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ा और कष्ट हो, देय क्षति-पूर्ति की राशि वह होगी जिसे दावा आयुक्त, मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखने के पश्चात्, उचित समझे।

बशर्ते कि उसी दुर्घटना में यदि एक से अधिक चोटें लगी हों तो ऐसी प्रत्येक चोट के लिए क्षतिपूर्ति देय होगी।

और बशर्ते कि ऐसी सभी चोटों के लिए कुल क्षतिपूर्ति दस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

(4) जब किसी चोट के लिए दी गयी क्षतिपूर्ति की राशि उस राशि से कम हो जो कि चोट ग्रस्त व्यक्ति के मरने पर क्षतिपूर्ति के रूप में देय होती और तद्नुसार चोट के परिणामस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के लिए देय राशि और पहले दी गयी राशि के अंतर के बराबर और क्षतिपूर्ति देय हो जायेगी।"

[सं० 73-टीजी II/1026/33/अध्यादेश]

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 20th December, 1978

S.O 895.—In exercise of the powers conferred by section 82-J of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Accidents (Compensation) Rules 1950, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Accidents (Compensation) Second Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 6 of the Railway Accidents (Compensation) Rules, 1950, for sub-rules (3) and (4) the following sub-rules shall be substituted, namely :—

"(3) The amount of compensation payable in respect of any injury [other than an injury specified in the Schedule or referred to in sub-rule (2)] resulting in pain and suffering, shall be such as the Claims Commissioner may, after taking into consideration all the circumstances of the case, determine to be reasonable.

Provided that if more than one injury is caused by the same accident, compensation shall be payable in respect of each injury.

Provided further that the total compensation in respect of all such injuries shall not exceed rupees ten thousand.

(4) Where compensation has been paid for any injury which is less than the amount which would have been payable as compensation if the injured person had died and the person subsequently dies as a result of the injury, a further compensation equal to the difference between the amount payable for death and that already paid shall become payable."

[No. 73-TGII/1026/33/Ordinance]

का० आ० 896—भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) के खण्ड 82-जे० द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा रेल दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) नियम, 1950 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को रेल दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) संशोधन नियम, 1978 कहा जाये।

(2) ये नियम सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. रेल दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) नियम, 1950 में :—

(i) नियम 3 में—

(क) धारा (ग) के बाद निम्नलिखित धारा अन्तर्विष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

"(घ) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है या प्रयोग किया है।"

(ii) नियम 4 के उप-नियम (1) में आये शब्द "जिला न्यायाधीश या जिला मजिस्ट्रेट" की शब्द "जिला न्यायाधीश या जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[सं० 73-टीजी II/1026/33/अध्यादेश]

पी० एन० मोहिले, सचिव

S.O. 896.—In exercise of the powers conferred by Section 32-J of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Accidents (Compensation) Rules, 1950, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Accidents (Compensation) Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railway Accidents (Compensation) Rules, 1950 :—

(i) in rule 3 —

(a) after clause (c) the following clause shall be inserted, namely :—

"(d) is or has exercised the powers of the Chief Judicial Magistrate."

(ii) in rule 4, in sub-rule (1) for the words "District Judge or District Magistrate", wherever they occur the words "District Judge or District Magistrate or Chief Judicial Magistrate" shall be substituted.

[No. 73-TGII/1026/33/Ordinance]

P. N. MOHILE, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979